A Daily News Magazine
भोपाल
शनिवार, 01 मार्च, 2025

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 173, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

पुतिन के प्रस्ताव को चीन ने क्यों नहीं किया स्वीकार ?

रजनीश कुमार

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने उस सुझाव पर सहमति दे दी है, जिसमें रूस और अमेरिका सैन्य बजट में बड़ी कटौती पर बात कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य बजट में 50 फ़ीसदी तक की कटौती पर बात हो रही है।

पुतिन ने कहा था, 'हम अमेरिका के साथ सैन्य खर्चों में कटौती को लेकर एक समझौते पर पहुँच सकते हैं। हम इसके खिलाफ़ नहीं हैं। यह ऐसा सुझाव है, जिससे मैं भी सहमत हूँ। अमेरिका अपने सैन्य बजट में 50 फ़ीसदी की कटौती करेगा और हम भी वैसा ही करेंगे। चीन भी चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है।'

लेकिन चीन को पुतिन का यह सुझाव पसंद नहीं आया।

25 फ़रवरी को समाचार एजेंसी एएफ़पी ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जिआन से पूछा कि पुतिन ने कहा है कि चीन भी इस प्रस्ताव में शामिल हो सकता है, क्या चीन इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा? 24 फ़रवरी की रात राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो बातचीत हुई थी, उसमें क्या इस प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई थी?

इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिन जिआन ने कहा, 'राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के बीच फोन पर जो बातचीत हुई, उसका रीडआउट जारी किया जा चुका है। आपने रक्षा खर्चों की बात की। हाल के वर्षों में वैश्विक रक्षा खर्चों में भारी बढ़ोतरी हुई है।'

'आँकड़ों के मुताबिक़ 2024 में वैश्विक रक्षा ख़र्च 2.43 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। वैश्विक रक्षा खर्चों में भारी बढ़ोतरी बढ़ती वैश्विक असुरक्षा के कारण है। सभी देश वैश्विक सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को और ख़ास कर बड़े देशों को विश्व शांति के लिए पहल करनी चाहिए।'

लिन जिआन ने कहा, चीन शांतिपूर्ण प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा, विकास से जुड़े हित और विश्व शांति बनाए रखने को रक्षा खर्चों को सीमित करने से जोड़ना उचित नहीं है। चीन की अपनी आत्मरक्षा रणनीति है, जिसके तहत हम राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के बीच समन्वय बनाते हैं। चीन किसी भी देश से हथियारों की होड़ नहीं कर रहा है। हमारी नीति दुनिया की स्थिरता और शांति के पक्ष में है।

चीन ने पुतिन के प्रस्ताव को स्वीकार तो नहीं किया लेकिन कुछ अहम बातें कहीं।

चीन ने कहा कि हाल के वर्षों में रक्षा खर्च दुनिया के कई इलाक़ों में तनाव के कारण बढ़ा है। चीन ने यह भी कहा कि बड़े देशों की ज़िम्मेदारी है कि शांति के लिए काम करें।

लिन से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका का सैन्य ख़र्च दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है और उसे मिसाल पेश करना चाहिए।

चीन ने कहा था कि दुनिया के 90 प्रतिशत परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। ऐसे में पहले इन्हें अपना परमाणु हथियार कम करना चाहिए तब बाक़ी देशों से कहना चाहिए।

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में असोसिएट प्रोफ़ेसर डॉ. राजन कुमार मानते हैं कि रक्षा खर्चों में कटौती के लिए पुतिन का तैयार होना बहुत हैरान नहीं करता है।

हथियारों की होड़ रोकने के लिए अमेरिका और रूस के बीच समझौते होते रहे हैं। रूस की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि वह अमेरिका के साथ हथियारों में होड़ कर सकता है। अब असली होड़ चीन और अमेरिका के बीच है लेकिन चीन ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। चीन को लगता है कि वह अब भी सैन्य ताक़त के मामले में अमेरिका से पीछे है और जब तक अमेरिका की बराबरी नहीं कर लेगा तब तक रक्षा बजट में कटौती के लिए तैयार नहीं होगा। रूस यह भी नहीं चाहता है कि चीन सैन्य ताक़त के रूप में महाशक्तिशाली बन जाए। चीन रूस का पड़ोसी है।

1969 में आमूर और उसुरी नदी के तट पर रूस और चीन के बीच एक युद्ध भी हो चुका है। इस युद्ध में रूस ने चीन पर परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली थी। इसमें चीन को क़दम पीछे खींचने पड़े थे। 2004 में दोनों देशों के बीच समझौते हुए और सेंट्रल एशिया के कई द्वीपों को रूस ने चीन को सौंप दिया था।

यूक्रेन और रूस की जंग में चीन आधिकारिक रूप से तटस्थ रहा है लेकिन इस दौरान रूस से गैस और तेल सबसे ज़्यादा चीन ने ही आयात किया है। यूरोप का कहना है कि रूस-यूक्रेन जंग के दौरान पुतिन को चीन से काफ़ी मदद मिली है।

लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फोर स्ट्रैटिजिक स्टडीज़ (आईआईएसएस) ने 12 फ़रवरी को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल वैश्विक सैन्य खर्च 2.46 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया था। 2024 में चीन का सैन्य खर्च 236 अरब डॉलर था। चीन ने 7.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। लेकिन कई विश्लेषक मानते हैं कि चीन का असली सैन्य ख़र्च आधिकारिक आँकड़ों से कहीं ज़्यादा होता है। हाल के दशकों में चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी का तेज़ी से आधुनिकीकरण किया है। शी जिनपिंग का लक्ष्य है कि जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का 2049 में 100 साल हो जाए तो एक वर्ल्ड क्लास आर्मी तैयार हो जानी चाहिए।

चीन की इसी तैयारी को अमेरिका चुनौती के रूप में देखता है। चीन की बढ़ती ताक़त से भारत, जापान और ताइवान भी चिंतित हैं। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है।

अमेरिका और रूस की बढ़ती क़रीबी पर दुनिया भर की नज़रें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भरोसा किस हद तक बढ़ता है, इसे लेकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है।

फ़रवरी 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने के बाद रूस और चीन में गर्मजोशी बढ़ी थी। पश्चिम के कड़े प्रतिबंधों के कारण रूस के पास चीन के क़रीब जाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन ट्रंप अब रूस को लेकर जिस तरह की उदारता दिखा रहे हैं, उससे पूरा समीकरण बदलता दिख रहा है।

ट्रंप का कहना है कि जब यूक्रेन की समस्या सुलझ जाएगी तब रक्षा खर्चों और परमाणु हथियारों को कम करने पर बात शुरू होगी। ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की तैयारी कर रहे हैं।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सोच समझकर करें पीएमएलए

यूएपीए में गिरफ्तारी की समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट का अदालतों को निर्देश, खींच दी न्यायिक समीक्षा की लक्ष्मण रेखा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल कानूनों के तहत गिरफ्तारी की समीक्षा बहुत सोच-समझकर करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के

ऐसे मामलों में कोर्ट को अपनी शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए

हित के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट) ,यूएपीए (अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट), फॉरेन एक्सचेंज, कस्टम्स ऐक्ट और जीएसटी जैसे खास कानूनों के संदर्भ में की। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में कोर्ट को अपनी शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। जस्टिस त्रिवेदी सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच का हिस्सा थीं। इस बेंच ने कस्टम और जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार देने वाले प्रावधानों को सही ठहराया। जस्टिस त्रिवेदी ने अपने अलग फैसले में कहा कि ऐसे मामलों (स्पेशल ऐक्ट के तहत गिरफ्तारी) में कोर्ट को सिर्फ यह देखना चाहिए कि कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन हुआ है या नहीं। मतलब, क्या अधिकारी कानून के तहत अधिकृत था। एससी जज ने कहा कि स्पेशल ऐक्ट्स खास उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, स्पेशल ऐक्ट्स के सख्त प्रावधानों को नरमी से देखने से कानून का मकसद पूरा नहीं होगा।

पीएमएलए, कस्टम्स ऐक्ट या फेरा के तहत अपराध बहुत गंभीर हैं। ये अपराध देश की वित्तीय व्यवस्था और संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से होनी चाहिए जिससे उनके उद्देश्य पूरे हों, न कि विफल। यह फैसला जांच एजेंसियों खासकर ईडी के लिए फायदेमंद हो सकता है। फैसले में कहा गया है, अगर कोर्ट बार-बार अधिकारियों के काम में दखल देगा, तो इससे गलत काम करने वालों का हौसला बढ़ेगा। और पीड़ितों, जो कि पूरा समाज और देश है, के साथ न्याय नहीं होगा। इस फैसले से जांच एजेंसियों को ताकत मिलेगी, क्योंकि कोर्ट के दखल की संभावना कम होगी। स्पेशल ऐक्ट क्या होते हैं, ये ऐसे कानून होते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति या अपराध से निपटने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें अक्सर सख्त प्रावधान होते हैं। उदाहरण के लिए,पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए है, यूएपीए आतंकवाद से और कस्टम्स ऐक्ट तस्करी से।

सुप्रभात

मैंने घर छोड़ा
ओढ़ा देश निकाला
जाने किसकी तलाश में अलग जगाया
विराने छानी जंगल-जंगल भटका
पागलपन मुझपर भीहड़ राहों का था
इस पागलपन के क्या थे जाने-माने
सब समझे मैं हूँ नये गगन का पाखी
सब समझे मैं कुछ नया ढूंढ़ कर लाया
सच तो यह है मैं आज बता दूँ सबको
मैं पँख पसार उड़ा जितनी दूर तक
वो सारा क्षितिज तुम्हारी बांहों का था
इन होठों से जितना जो कुछ रस पाया, उसको ही
अपना गीत बनाकर गया
अब शाम उतर आई है
पथ धुंधलाया धीरे-धीरे उदास अँधियारा छाया
राहें पगडंडी सब होती जाती गुम
अब मेरे और करीब, और करीब चलो तुम
जिस मन की मधुराई, तन की उजराई
मुझ को सम्भालकर इस मुकाम तक लाई
वो क़दम-क़दम गढ़ती उजयार चलेगी
ये यात्रा जन्म-जन्म के पार चलेगी।

– धर्मवीर भारती

उत्तराखंड में टूटा बर्फ का पहाड़

फंसीं 41 जिंदगी

16 लोगों को निकाला, सड़क से बर्फ हटाने गए थे

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार सुबह 8 बजे एवलांच की वजह से 57 मजदूर बर्फ में दब गए। घटना चमोली के माणा गांव में हुई। बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन की टीम चमोली-बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने का काम कर रही थी। उसी दौरान बर्फ का पहाड़ टूटा और मजदूर दब गए। अब तक 16 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 41 को निकालने का काम जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरआई की टीमें मौके पर हैं। मौसम विभाग

ने 28 फरवरी की देर रात तक उत्तराखंड में भारी बारिश (20 मिमी तक) का अलर्ट जारी किया है। चमोली के एसपी संदीप तिवारी ने बताया कि घटनास्थल पर लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, इसलिए हम हेलीकॉप्टर नहीं भेज पा रहे हैं। आवाजाही मुश्किल है। सैटेलाइट फोन उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए हम उनसे बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। एनडीआरएफ की एसपी रिधिमा अग्रवाल ने कमांडेंट के हवाले से बताया कि घटना बद्रीनाथ धाम के पास की है। एक टीम जोशीमठ से रवाना हो चुकी है। लामबगड़ में सड़क ब्लॉक है।

भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में गढ़े हैं नए कीर्तिमान : मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री द्वारा विज्ञान आधारित कार्यप्रणाली, जिज्ञासु प्रवृत्ति और नवीनतम तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहन से देश को मिली उपलब्धि

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विज्ञान के आधार पर व्यवस्थित कार्यप्रणाली, जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन और नवीनतम तकनीकों के उपयोग ने देश को विश्व के शीर्ष राष्ट्रों में गिने जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन से ही यह उपलब्धि संभव हो पाई है। राज्य सरकार शिक्षा सहित शासकीय कार्य प्रणाली और सामान्य व्यवस्थाओं के संचालन में विज्ञान का अधिक से अधिक उपयोग कर आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 'विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाने' की थीम पर भोपाल में विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और युवाओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर तथा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पूर्व उन्होंने नोबल पुरूस्कार से सम्मानित महान वैज्ञानिक श्री सीवी रमन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्टेम एजुकेशन' का विज्ञान भवन में शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेंटर में प्रस्तुत मॉडल तथा विद्यार्थियों को विज्ञान के विभिन्न सिद्धांत, सरलता से समझाने में सहायक उपकरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल और नवाचारों के संबंध में उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टीकमगढ़ से आए प्रगतिशील कृषक श्री पूरनलाल कुशवाहा से भेंट कर उनके द्वारा सिंचाई के लिए विकसित किए गए पवन और पानी से चलने वाले पंप का अवलोकन कर जानकारी भी प्राप्त की।

उज्जयिनी में विक्रमोत्सव

वास्तु सिद्धान्तों के उदाहरण हैं शैव परम्परा के देवालय

उज्जैन से
डॉ. जफर महमूद

भगवान शिव पशुपति हैं उनके अनेक स्वरूप हैं। शास्त्रों में शिवतत्व का विवेचन विस्तृत से किया गया है। जो शाश्वत, विशुद्ध शीघ्र कल्याण करने वाले हैं , वह शिव हैं। शैव परंपरा में वास्तुशास्त्रीय तत्व सदैव गंवेषणा का विषय रहा है। भगवान शिव का स्वरूप और उनके अस्त्र डमरू, त्रिशूल आदि वास्तुशास्त्र और कल्याण के प्रतीक हैं।

ये विचार विक्रमोत्सव 2025 अंतर्गत 'शैव परम्परा एवं वास्तु विज्ञान'विषय पर आधारित दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (काठमांडू) के प्रो. काशीनाथ न्यौपाने ने कही। संगोष्ठी महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ तथा वास्तु विभाग, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गयी। मुख्य अतिथि प्रो. न्यौपाने ने सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल की चर्चा करते हुए कहा कि उनके नवरत्न संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। विक्रमादित्य द्वारा स्थापित विक्रम सम्वत् भारत के साथ ही नेपाल में भी अधिमान्य है।

विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. बालकृष्ण शर्मा ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान शिव का स्वरूप अनिष्ट का परिहारक है। उनके द्वारा धारित चिह्न वास्तुजन्य दोषों का शमन करने में समर्थ हैं। उन्होंने शैव आगम और राजा भोज द्वारा विरचित समरांगण सूत्रधार की चर्चा करते हुए कहा कि रिद्धि-सिद्धि की प्राप्ति के लिए वास्तु शास्त्रीय तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है। बिना वास्तु के शुभ-अशुभ लक्षणों का बोध होना संभव नहीं है। अध्यक्षीय उद्बोधन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलगुरु, प्रो. विजयकुमार सी.जी. ने भारतीय संस्कृति में शैव आगम और इस दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा में कहा कि शिव ही जगत का मूल चेतन तत्व हैं ,जो बंधन तथा मुक्ति का कारण हैं। उन्होंने मंत्र वास्तु, शैवमत, शिव की शाश्वत सत्ता और अनेक दर्शन और मतों को प्रस्तुत करते हुए विक्रमोत्सव के भव्य आयोजन की बधाई दी। अथिति परिचय डॉ. तुलसीदास परौहा ने दिया विषय प्रवर्तन संयोजक डॉ. शुभम शर्मा ने प्रस्तुत किया। आभार कुलसचिव प्रो. दिलीप सोनी ने माना। संचालन डॉ. विजय कुमार ने किया। कार्यक्रम में नेपाल, म्यांमार तथा वियतनाम के शिक्षाविद् सहित भारत के विभिन्न भागों के विद्वान, छात्र तथा शोधार्थी उपस्थित थे।

आदि-अनादि पर्व- डमरू वादन के साथ मलखम्ब का प्रदर्शन

महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जयिनी विक्रम व्यापार मेला मंच पर मुकेश शास्त्री द्वारा डमरू वादन और योगेश मालवीय के निर्देशन में मलखम्ब का प्रदर्शन किया गया। महाकाल कॉरिडोर के ओपन मंच पर आतिशी तिवारी एवं साथियों द्वारा शिव केन्द्रित भक्ति गायन प्रस्तुत किया गया।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 22 °c | न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार,01 मार्च 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

पुणे में सरकारी बस में रेप केस का आरोपी अरेस्ट

गन्ने के खेत में छिपा था, पानी पीने गांव में आया,लोगों ने पुलिस को खबर कर दी

पुणे (एजेंसी)। पुणे में खड़ी बस में 26 साल की महिला के साथ हुए रेप का आरोपी महाराष्ट्र के शिरूर तहसील के केगुनाट गांव से गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम ब्रांच पुणे के डीएसपी निखिल पिंगले ने बताया- गन्ने के खेत से आरोपी को देर रात गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के पूरे प्रोसेस में गांववालों ने हमें मदद की। उन्होंने ही बताया कि आरोपी गुनात गांव में आया है। रात में उसने एक घर से पीने का पानी और खाना मांगा। इस दौरान लोगों ने

उसे पहचान लिया और जानकारी पुलिस को दे दी। आरोपी को पकड़ने में भी लोगों ने मदद की। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा- आरोपी बीती रात 1.10 बजे गुनात गांव से पकड़ा गया। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक स्पेशल वकील नियुक्त किया जाएगा। हम केस को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे की जांच के लिए आरोपी को पुणे भेज दिया गया है। आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे ने 25 फरवरी को सरकारी स्वारगेट डिपो में इस वारदात को अंजाम दिया था।उस पर 1 लाख रुपए का ईनाम था।

संभल जामा मस्जिद में नहीं होगी रंगाई पुताई

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मुस्लिम पक्ष को लगा झटका

प्रयागराज (एजेंसी)। संभल जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई करवाने की अनुमति नहीं दी। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने शुक्रवार सुबह अपनी रिपोर्ट सौंपी। एएसआई ने रिपोर्ट में कहा- मस्जिद की पेंटिंग अभी ठीक है। इसके बाद हाईकोर्ट ने एएसआई की निगरानी में तत्काल साफ-सफाई कराने का आदेश

दिया । मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने का 4 मार्च तक का समय दिया। हाईकोर्ट 4 मार्च को इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। दरअसल, 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा था- हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। इस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी।

मणिपुर में फिर भड़के कुकी संगठन, दे दी वॉर्निंग

कहा-इंफाल के लिए घातक हो सकती है अरमबाई टेंगूल से बातचीत

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर में कुकी संगठनों में से कुछ ने संयुक्त बयान जारी कर अरमबाई टेंगूल के कार्यकर्ताओं के इस कदम की निंदा की है। उनका कहना है कि केवल संवेदना हासिल करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। कुकी संगठनों ने कहा कि इंफाल वैली में 6 हजार से ज्यादा हथियार लूटे गए थे। वहीं 300 हथियारों का सरेंडर किया जाना कोई बड़ी संख्या नहीं है। यह केवल जनता में छवि सुधारने का एक तरीका है। मणिपुर के राज्यपाल सरकार की छवि ठीक करने के लिए यह सब कर रहे हैं। कुकी संगठनों ने कहा कि अरमबाई टेंगोल का राज्यपाल करना इंफाल की जनता के साथ अन्याय है। वे खुद मिलकर अपनी समस्याएं रखना चाहते थे लेकिन बीच में टेंगोल ने दखल दे दिया। अब यह इंफाल के लिए घातक हो सकता है। वहीं राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गवर्नर अजय भल्ला ने उग्रवादियों से लूटे गए हथियारों को सरेंडर करने की तारीख दे दी थी। इसके बाद बड़ा हथियारों का जखीरा सुरक्षाबलों और पुलिस के पास वापस आ गया है। मणिपुर में अरमबाई टेंगोल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को इंफाल में प्रथम मणिपुर राइफल परिसर में कुल 307 हथियारों में से 246 हथियार सौंपे, जबकि पहाड़ी और घाटी जिलों में अन्य स्थानों पर 61 और हथियार सौंपे गए। पुलिस ने बताया कि अरमबाई टेंगोल के सदस्यों ने आज मणिपुर सरकार के सामने हथियार सौंपे। पुलिस ने बताया कि स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के लिए दी गई सात दिन की अवधि समाप्त होने के बाद, सभी संबंधित व्यक्तियों,विशेषकर युवाओं से दृढ़तापूर्वक अनुरोध किया जाता है।

तेलंगाना टनल हादसा

अंदर फंसे मजदूरों के जिंदा बचने की संभावना कम

रेलवे की टीमें भी रेस्क्यू में जुटी, 22 फरवरी से 8 मजदूर फंसे हैं

नागरकुर्नूल (एजेंसी)। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था। घटना को 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन टनल में फंसे 8 मजूदरों को अब तक नहीं निकाला जा सका है।

रेस्क्यू जारी है। शुक्रवार को साउथ सेंट्रल रेलवे की 2 टीमें भी रेस्क्यू के लिए पहुंचीं। टीम भारी धातुओं को प्लाज्मा कटर और ब्रॉक कटिंग मशीन जैसे आधुनिक उपकरणों से काटने रास्ते से हटा रही है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी मौके पर पहुंचे हैं।

ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की मदद से मलबे में दबे मजदूरों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी मजदूर के जीवित मिलने की संभावना बहुत कम लग रही है। नागरकुरनूल के एसपी वैभव गायकवाड़ ने बताया कि मलबा हटाने और लोहे की छड़ों की कटिंग का काम लगातार जारी है। टनल के पानी को बाहर निकालने का काम चल रहा है।

अब सिद्धारमैया ने अमित शाह से मांग ली एक गारंटी

परिसीमन विवाद: कहा-दक्षिण भारत के 5 राज्यों का डर तभी खत्म होगा

बेंगलुरु (एजेंसी)। लोकसभा सीटों का परिसीमन होने के बाद तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसे लेकर राजनीति तेज है और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तो राज्य के सभी दलों की मीटिंग बुलाई है। यही नहीं अब यह मसला जोर पकड़ता जा रहा है और कर्नाटक के सीएम एम. सिद्धारमैया ने भी इसे लेकर केंद्र से गारंटी मांगी है। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह की उस बात को लेकर भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु या फिर दक्षिण के किसी अन्य राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। सिद्धारमैया ने कहा कि यदि 2025 की जनगणना के अनुसार ही परिसीमन हुआ तो फिर दक्षिण भारत के 5 राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी। पहले भी जनसंख्या के अनुसार ही परिसीमन होता रहा है और यदि इस बार भी वही फॉर्मूला रहा तो हमें नुकसान होगा। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से एक गारंटी मांगी कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाए। सिद्धारमैया ने कहा, यह तथ्य है कि यदि वर्तमान जनसंख्या के अनुसार परिसीमन किया गया तो फिर दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान होगा। इस अन्याय को रोकने के लिए परिसीमन 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि होम मिनिस्टर अमित शाह कहें कि 1971 के आंकड़ों का ही प्रयोग किया जाएगा तो माना जा सकता है कि दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान नहीं होगा। दरअसल एमके स्टालिन की ओर से जाहिर की गई चिंताओं पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा था कि दक्षिण भारत के किसी भी राज्य को सीटों का नुकसान नहीं होगा। एमके स्टालिन की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था और अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में भी यह जोर पकड़ रहा है। दरअसल ऐसी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उत्तर में सीटें बहुत ज्यादा होंगी।

देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में फैला बर्ड फ्लू

- एमपी के छिंदवाड़ा से लिए सैंपल की रिपोर्ट पॉजीटिव
- मटन-चिकन और अंडे की खरीदी-बिक्री पर लगी रोक

छिंदवाड़ा (एजेंसी)। छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू से पालतू बिल्लियों की मौत के बाद चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। 30 दिन के लिए मटन-चिकन और अंडों की खरीदी-बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही संक्रमित क्षेत्र की सभी मटन और चिकन की दुकानों को सील कर दिया गया है। दरअसल, जिले में पिछले दिनों करीब 18 बिल्लियों की मौत हो गई थी। जिसके बाद 15 जनवरी को 4 और 22 जनवरी को 3 बिल्लियों के सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरलॉजी भेजे गए थे। 31 जनवरी को आई रिपोर्ट में इनमें से दो पालतू बिल्लियों के सैंपल एच5एन1 (बर्ड फ्लू) पॉजीटिव मिले थे। देश में ऐसा पहली बार है, जब घरेलू बिल्लियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीएस पक्षवार ने बताया कि मृत बिल्लियों

को कच्चा मांस जिन दुकानों से खिलाया गया था, उन 2 दुकानों विक्की चिकन सेंटर और नावेल्टी सेंटर के यहां सैंपलिंग की गई, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। प्रभावित क्षेत्र में प्रोटोकॉल का पालन कर संबंधित क्षेत्र में मटन, मुर्गी और अंडों को नष्ट किया गया। साथ ही मार्केट में इनके क्रय विक्रय पर पाबंदी लगा दी गई थी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल हो सुधार: भारत

- भारत ने यूएन के सदस्यों को लगाई कड़ी फटकार
- आतंकवादियों के रक्षक चीन को भी खूब सुनाया

न्यूयॉर्क (एजेंसी)। भारत ने गुरुवार 27 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के सहायक बॉडीज के कामकाज के तरीकों में तत्काल सुधार का आह्वान किया है। भारत ने यूएनएससी के निकायों में ज्यादा पारदर्शिता लाने का आग्रह किया है। भारत ने आतंकवादी संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट में डालने के प्रस्तावों को

अस्वीकार करने या रोकने के फैसलों के बारे में बरती जाने वाली गोपनीयता की आलोचना की है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने इस प्रथा को 'छिपा हुए वीटो' बताया है। उन्होंने तत्काल इसमें सुधार लाने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि कई मौकों पर चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों का समर्थन किया।

अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं, मोहल्ला क्लीनिक से शौचालय भी मिले गायब

कैग रिपोर्ट में दिखी दिल्ली की 'आपदा', कई जगह एंबुलेंस भी नदारद

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा कैग रिपोर्ट की हो रही है, रेखा सरकार की तरफ से विधानसभा सत्र के दौरान कुल 14 फाइलें पेश की गई हैं। वहां भी राजधानी की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई हैरान कर देने वाले दावे हुए हैं। कैग की रिपोर्ट से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कई अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं थे, एंबुलेंस की संख्या भी काफी कम, इसके ऊपर मोहल्ला क्लीनिक में शौचालय गायब रहे। कैग रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 14 ऐसे अस्पताल हैं जहां अभी तक आईसीयू बेड नहीं है, 12 ऐसे अस्पताल सामने आए हैं जहां एंबुलेंस की कोई सुविधा नहीं। इसके ऊपर कई ऐसे मोहल्ला क्लीनिक पाए गए जहां कोई शौचालय

ही नहीं है। भारत सरकार से कोविड के दौरान जो फंड मिले थे, उसे लेकर भी कैग ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि उस पैसे को पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया गया। वो आंकड़े कहते हैं कि केंद्र से दिल्ली की आप सरकार को 787.91 करोड़ रुपये की राशि मिली थी। लेकिन आप सरकार मात्र 582.84 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाएगी, यानी कि काफी पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यह मायने इसलिए रखता है क्योंकि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान काफी तबाही देखने को मिली थी।

जन्म से हिंदू हूं, इसलिए महाशिवरात्रि कार्यक्रम में गया

- कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बोले-अमित शाह भी थे शामिल
- कांग्रेस सचिव बोले- डिप्टी सीएम राहुल का मजाक उड़ाने वालों के साथ

चेन्नई (एजेंसी)। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार 26 फरवरी को ईशा फाउंडेशन की तरफ से कोयंबटूर में आयोजित महाशिवरात्रि कार्यक्रम में गए थे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पीवी मोहन ने शिवकुमार की कोयंबटूर यात्रा पर निशाना साधा। पीवी मोहन ने सोशल मीडिया पर लिखा- शिवकुमार एक ऐसे व्यक्ति के निमंत्रण पर गए, जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है। पीवी मोहन के आरोपों का जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा- मैं एक हिंदू हूं। मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं और मैं एक हिंदू के रूप में मर जाऊंगा, लेकिन मैं सभी धर्मों से प्यार करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। शिवकुमार बोले- सद्गुरु जग्गी वासुदेव एक महान इंसान हैं शिवकुमार ने सद्गुरु के कार्यक्रम में जाने को लेकर कहा कि ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु जग्गी वासुदेव आए

और मुझे (कोयंबटूर में शिवरात्रि समारोह के लिए) आमंत्रित किया। वे मैसूर से हैं। वे महान व्यक्ति हैं और मैं उनके ज्ञान और कद की प्रशंसा करता हूं, लेकिन कई लोग उनकी आलोचना करते हैं।

योगी सरकार का कुंभ का आयोजन सराहनीयः महाकुंभ के बारे में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से उन्होंने (योगी सरकार) इसे आयोजित किया, मैं उसकी सराहना करता हूं। यह कोई छोटा काम नहीं है। यहां-वहां कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ट्रेनों के कारण भी समस्याएं हो सकती हैं। मुझे खामियां निकालना पसंद नहीं है। यह बहुत संतोषजनक है। भाजपा से किसी तरह की साठगांठ नहींः भाजपा के साथ साठगांठ के आरोपों का जवाब देते हुए शिवकुमार ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। उन्होंने कहा,कांग्रेस पार्टी में सभी को साथ लेकर चलने का सिद्धांत है। महात्मा गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी यही किया।

एमपी और छत्तीसगढ़ के किसानों को कृषि सम्मान अवॉर्ड

भोपाल। दिल्ली प्रेस की कृषि पत्रिका फार्म एन फूड द्वारा भोपाल के रवींद्र भवन में राज्य स्तरीय फार्म एन फूड कृषि सम्मान अवॉर्ड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के 150 से ज्यादा किसान और कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए और खेती में नवाचार और तकनीकी के जरिए विभिन्न 17 श्रेणियों में बदलाव लाने वाले तकरीबन 30 किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विज्ञान केंद्रों को राज्य स्तरीय फार्म एन फूड कृषि सम्मान अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मध्य प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, 'भारत गांव में, खेत में और खलिहान में बसता है' हमें खेती पर और किसान पर ध्यान देना होगा। हमें फूड प्रोसेसिंग पर जोर देना होगा। 'नदी जोड़ो अभियान' इस में सहायक है। खेत से ही इस देश को मजबूत करने की इबारत लिखी जा सकती है। सरकार का यही उद्देश्य की खेती मुनाफे का धंधा बने।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और मध्य प्रदेश सरकार में कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेंटवाल ने कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और किसान हमेशा सीखता है। वह नवाचार करता है, नई तकनीक इस्तेमाल करता है। जब किसान के पास पर्याय खाद होगी और दूसरी सुविधाएं मुहैया होंगी, वह इस क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा।

विजेता किसानों में रतलाम के कपिल धाकड़ को बेस्ट यंग फार्मर अवॉर्ड दिया गया। महासमुंद के मिलन सिंह विश्वकर्मा और भोपाल के मनोहर पाटीदार को बेस्ट मेल फार्मर अवार्ड मिला। ग्वालियर की निशा निरंजन को बेस्ट फीमेल फार्मर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जबकि भोपाल के गीता प्रसाद पाटीदार, शाजापुर के जयनारायण पाटीदार और टीकमगढ़ के पूरन लाल कुशवाहा को बेस्ट फार्मर अवॉर्ड इन इनोवेटिव फार्मिंग अवॉर्ड दिया गया।

अशोकनगर के खुमान सिंह रघुवंशी, भिंड के रामगोपाल सिंह, दंतेवाड़ा के जयलाल यादव को बेस्ट फार्मर अवार्ड इन आर्गेनिक/नेचुरल फार्मिंग का अवॉर्ड मिला। उज्जैन के अश्विनी सिंह चौहान, नारायणपुर के सुरेंद्र कुमार नाग को बेस्ट फार्मर अवॉर्ड इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग दिया गया।

दिल्ली प्रेस के कार्यकारी प्रकाशक अनंत नाथ ने कहा, कृषि जगत हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। इसी क्षेत्र में किसानों के योगदान को लोगों को बताने के लिए हम ने फार्म एन फूड पत्रिका को शुरू करने की सोची और यह भी माना कि यह किसान समाज को जोड़ने की कड़ी है। मैं खुद को कृषि का छात्र मानता हूं। कोरोना काल मे घर पर एक किचन गार्डन बनाया था जो अब भी बरकरार है। हमारे जो आज के विजेता हैं वे बहुत मेहनती हैं और वे इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अचीव कर रहे हैं। मेरी अपील है कि किसान इस पत्रिका से जुड़े रहें ताकि हमारी संस्था कृषि जगत में होने वाली हर बात को जनजन तक पहुंचा सकें।

इस सम्मान समारोह में पुरस्कृत किसानों के साथ-साथ कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य कृषि संस्थानों के वैज्ञानिक, अन्य शासकीय और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मंच संचालन विजी श्रीवास्तव ने किया।

एमपी में बादल-बारिश के आसार

4 मार्च से बदल सकता है मौसम, इससे पहले 2 से 4 डिग्री बढ़ा रहेगा पारा

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में मार्च के पहले सप्ताह में बादल छाने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। 2 मार्च से पश्चिम-उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव हो रहा है। जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। खासकर 4 मार्च से इंदौर, ग्वालियर, चंबल हिस्से में कहीं-कहीं मौसम बदला हुआ रह सकता है। इससे पहले दिन-रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

फरवरी में मौसम का मिला-जुला असर रहा। शुरुआती दिनों में ही तेज ठंड पड़ी, लेकिन दूसरे सप्ताह से ठंड जैसी गायब सी हो गई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत कई शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से अधिक ही रहा। वहीं, दिन में 34 डिग्री तक पहुंच चुका है। फरवरी के आखिरी दिन शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना था,लेकिन मार्च के पहले सप्ताह में मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है।

दो दिन बाद असर

उत्तर-पश्चिमी भारत में सक्रिय होने वाले वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर प्रदेश में 2 दिन बाद यानी, 4 मार्च से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सकुर्लेशन सिस्टम भी एक्टिव है। इस कारण भोपाल समेत कई शहरों में बादल छाए रहे।

रात के पारे में बढ़ोतरी, 10 डिग्री के पार पहुंचा

प्रदेश में पांच दिन तक तेज ठंड पड़ी। इस वजह से पचमढ़ी समेत कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे ही रहा, लेकिन बुधवार-गुरुवार की रात में पारे में फिर से बढ़ोतरी होने लगी। कई शहरों में पारा 2 से 4 डिग्री तक बढ़ गया। पचमढ़ी में 10.2 डिग्री, कल्याणपुर में 10.3 डिग्री, शाजापुर के गिरवर में 11.2 डिग्री, उमरिया में 11.3 डिग्री, अशोकनगर के आंवरी में 11.6 डिग्री और मंडला में पारा 12 डिग्री तक दर्ज किया गया। इधर, गुरुवार को दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

6 लाख 73 हजार से अधिक बिजली उपभोक्ताओं ने कराई ई-केवायसी

अब 'उपाय' ऐप से भी करा सकेंगे केवायसी

भोपाल(नप्र)। राज्य की लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को ईकेवायसी कराना अनिवार्य है। उपभोक्ता मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय ऐप से भी ईकेवायसी करा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध 'उपाय' ऐप डाउनलोड कर बिजली उपभोक्ता समग्र केवायसी में अपना उपभोक्ता क्रमांक एवं समग्र क्रमांक दर्ज करने के बाद लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर केवायसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। केवायसी प्रक्रिया में अब तक 06 लाख 73 हजार 534 उपभोक्ताओं ने सफलतापूर्वक केवायसी करा ली है।

कंपनी ने बताया है कि नर्मदापुरम ग्रामीण क्षेत्र में 71 हजार 940, बैतूल ग्रामीण में 91 हजार 012, राजगढ़ ग्रामीण में 51 हजार 223, शहर वृत्त भोपाल में 61 हजार 271, भोपाल ग्रामीण में 38 हजार 656, गुना ग्रामीण में 32 हजार 353, विदिशा ग्रामीण में 49 हजार 230, सीहोर ग्रामीण में 24 हजार 130, ग्वालियर ग्रामीण में 21 हजार 086, शहर वृत्त ग्वालियर में 46 हजार 642, अशोकनगर ग्रामीण में 25 हजार 737, दतिया ग्रामीण में 25 हजार 233, रायसेन ग्रामीण में 44 हजार 009, शिवपुरी ग्रामीण में 25 हजार 791, हरदा ग्रामीण में 20 हजार 964, श्योपुर ग्रामीण में 09 हजार 652, मुरैना ग्रामीण में 23 हजार 730 एवं भिण्ड ग्रामीण में 10 हजार 875 बिजली उपभोक्ताओं की केवायसी की गई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली संबंधी व्यक्तिगत विवरण को कंपनी के रिकार्ड में अपडेट करने के लिए नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी द्वारा नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया के तहत बिजली उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे समग्र आईडी, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता इत्यादि की जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया से बिजली उपभोक्ताओं को जहां राज्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साथ ही केवायसी से वास्तविक उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन एवं उनके भार की स्थिति का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे कंपनी कार्य क्षेत्र में विद्युत संरचनाओं के भविष्य में विस्तार की योजना बनाने में आसानी होगी। केवायसी होने से कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की सही पहचान और मोबाइल नंबर को सटीक रूप से टैग करने में मदद मिलेगी, जिससे कंपनी की सेवाओं का सुचारू संचालन।

एनएचएम की नवीन संविदा नीति से चिकित्सा कार्मिकों को मिलेगा बेहतर कार्य वातावरण : उप मुख्यमंत्री

वेतन वृद्धि, मातृत्व और पितृत्व अवकाश, सेवा सुरक्षा के प्रावधान नवीन नीति में शामिल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीन संविदा कर्मचारी नीति-2025 का निर्धारण संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए किया गया है। नवीन नीति से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में स्थायित्व आएगा और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। इस नीति का लाभ 32 हज़ार संविदा कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा और उनके परिवारों सहित लगभग 1.5 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने में सहायक होगा। उन्होंने समस्त संविदा कर्मचारियों से अपील की है कि सभी समर्पित भाव से सेवा करें, जिससे प्रदेश के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें।

एनएचएम की नवीन नीति में संविदा कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। अब कर्मचारियों को हर वर्ष अनुबंध के नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध वार्षिक सेवा आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई है। कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए एक अपीलीय अनुक्रम स्थापित किया गया है। संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का अधिकार केवल मिशन संचालक एनएचएम के पास होगा और यह केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद ही किया जा सकेगा।

नवीन नीति में वेतन वृद्धि को भी एक सुव्यवस्थित ढांचे में लाया गया है। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर नियमित वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को नियुक्ति के समय प्रसव के छह सप्ताह बाद (सातवें सप्ताह से) कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे वे मातृत्व के शुरुआती दिनों में समुचित देखभाल प्राप्त कर सकेंगी। इसी तरह, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश के प्रावधान भी संविदा कर्मचारियों के लिए लागू किए गए हैं।

आकस्मिक परिस्थितियों में सहायता के लिए अनुकंपा नियुक्ति और एक्स-ग्रेशिया के प्रावधान

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की सुचारु व्यवस्था के लिए संविदा कर्मचारियों को अंतर-जिला स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की गई है। जिला स्वास्थ्य समिति को जिले में स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक स्पष्ट शिकायत निवारण अनुक्रम निर्धारित किया गया है। आकस्मिक परिस्थितियों में परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति और एक्स-ग्रेशिया सहायता राशि के प्रावधान किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार विशेष अवकाश की सुविधा भी संविदा कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी।

नवीन नीति में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच चल रही हो, तो उसे 50 प्रतिशत वेतन प्रदान किया जाएगा। स्थानांतरण प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। साथ ही, वेतन असमानता की समस्या को दूर करते हुए सभी संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन समानता सुनिश्चित की गई है।

होटल के खाने में मिला कांच का टुकड़ा

भोपाल में मैरिज एनिवर्सरी मनाने गया था कपल, सॉरी पर कहा-गला कट जाता तो?

भोपाल (नप्र)। भोपाल के एक होटल के खाने में कांच का टुकड़ा निकला है। वीडियो सामने आने के बाद खाद्य औषधि एवं प्रशासन विभाग ने जांच शुरू की है। वीडियो में महिला ग्राहक जहांनुमा पैलेस का जिक्र कर रही है। जिसमें वे मैनेजर और शेफ से बात कर रही है। हालांकि, जहांनुमा पैलेस की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है।

वीडियो में ये कह रही महिला ग्राहक

वीडियो में महिला कह रही है कि हम जहांनुमा पैलेस में बैठे हैं। यहां पर खाने में कांच सर्व किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? इस पर शेफ सॉरी कहते हैं तो महिला कह रही है कि गला कट जाता तो आपके सॉरी का हम क्या करते? आपके 'आई एग्री' से कुछ नहीं होता। यदि खाने लायक है तो खाकर बताइए। करीब 1 मिनट के वीडियो के आखिरी में शेफ ने मामले को सुलझाने की बात कही।

मैरिज एनिवर्सरी मनाने गया था कपल

मीनल राय ने बताया कि मेरी बहन और जीजाजी की गुरुवार को मैरिज एनिवर्सरी थी। इस दौरान वे परिवार के साथ जहांनुमा पैलेस गए थे। उन्होंने खाना ऑर्डर किया। जैसे ही वह टेबल पर आया, उसमें कांच का टुकड़ा मिला। इस पर आपत्ति भी जताई। बहन ने ही वीडियो बनाए। हालांकि, वे बिना खाना खाए ही वापस लौट गए।

फूड इंस्पेक्टर बोले- जांच करवा रहे

इस मामले में सीनियर फूड इंस्पेक्टर देवेंद्र दुबे ने बताया कि, वीडियो सामने आया है। लिखित शिकायत नहीं मिली है। फिर भी जांच करवाएंगे।

चलती बाइक पर खड़े होकर राहगीरों को फ्लाइंग किस

भोपाल में युवती ने किया डांस, साथी युवकों ने लोगों से की अभद्रता

भोपाल (नप्र)। भोपाल के वीआईपी रोड पर एक बाइक पर दो लोगों के बीच खड़ी युवती का डांस करते वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार में युवती ने राह चलते लोगों को फ्लाइंग किस भी दी। इतना ही नहीं वीडियो बनाने पर उसके साथी युवकों ने राह चलते लोगों से अभद्रता की।

इधर, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देख अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। बाइक नंबर के आधार पर युवती सहित उसके साथियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द तीनों को गिरफ्तार किया जाएगा। बाइक पर दो लोगों के बीच खड़ी युवती का डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

काले रंग की बाइक पर खड़ी थी युवती- ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल डीसीपी बसंत कौल ने बताया कि वीआईपी रोड पर काले रंग की बाइक पर सवार युवती और दो युवकों का वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। लड़की तेज रफ्तार में चलती बाइक पर खड़ी नजर आ रही है।

राहगीरों ने इस वीडियो को फिल्माया है। वीडियो में दिख रही बाइक के नंबर के आधार पर जल्द तीनों को गिरफ्तार कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

देश की पहली मालवी प्रेम कहानी का भोपाल में ऑडिशन

भोपाल। राठौर फिल्म एंड एंटर टेनमेंट के बैनर तले मालवा की पहली रोमांटिक फिल्म 'थारो म्हारो प्रेम' का ऑडिशन भोपाल क्षेत्र के रंगकर्मियों के लिए नाइन मसाला रेस्टोरेंट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सुश्री मालती राय महापौर भोपाल ने किया,इस अवसर पर कई कलाकार अजय पॉल नंदू , राजेंद्र कानूनगो आदि कलाकार उपस्थित रहे ,इस अवसर पर मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार डॉ.नवीन आनंद जोशी, निशा गर्ग जी, आलोक गर्ग तथा कई गणमान्य पत्रकारों प्रेस वार्ता में चर्चा की, निर्माता निर्देशक राजेंद्र राठौर द्वारा फिल्म की संपूर्ण जानकारी दी। इस फिल्म के मंदसौर उज्जैन में ऑडिशन हो चुके हैं भोपाल के बाद रतलाम में होगा ,फिर झाबुआ होगा। इस फिल्म में मालवा के स्थानीय कलाकारों को प्रमुखता से लिया जा रहा है साथ ही साथ बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार फिल्म में रहेंगे । पिछले सप्ताह फिल्म का प्रोमो मंदसौर लदुना पशुपतिनाथ देव डूंगरी माताजी पर फर्स्ट शेड्यूल के संपन्न किया गया, राजेंद्र राठौड़ द्वारा पूर्व में फिल्म कुंवारापुर बनाई गई थी फिल्म को टैक्स फ्री करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सिनेमा को विशेष अनुदान दिया जाए । मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है, राजेंद्र राठौड़ द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य शासन को धन्यवाद दिया।निर्देशक राजेंद्र राठौड द्वारा इस अवसर पूरी फ़िल्म की जानकारी दी।

'सुबह सवेरे' समाचार-पत्र के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित विवरण

घोषणा

फार्म-4

1.	प्रकाशन स्थल	: भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	: दैनिक
3.	मुद्रक का नाम	: उमेश त्रिवेदी
	क्या भारत का नागरिक है	: हां
	पता	: डी-100/46, शिवाजी नगर, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	: उमेश त्रिवेदी
	क्या भारत का नागरिक है	: हां
	पता	: डी-100/46, शिवाजी नगर, भोपाल
4.	संपादक का नाम	: उमेश त्रिवेदी
	क्या भारत का नागरिक है	: हां
	पता	: डी-100/46, शिवाजी नगर, भोपाल
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	: सुबह सवेरे मीडिया एलएलपी बी-208, शाहपुरा, भोपाल-(म.प्र.)-462016

मैं उमेश त्रिवेदी एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

हस्ताक्षर
उमेश त्रिवेदी
(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

दिनांक : 28-02-2025

मप्र में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का आदेश

अधिकतम 2434 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि, टेक्सटाइल-फुटवियर श्रमिकों को इंतजार

भोपाल (नप्र)। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद श्रम विभाग ने मध्य प्रदेश के 21 लाख श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। श्रमिकों को यह लाभ मार्च 2025 से ही मिलेगा। उनके वेतन में 1625 से 2434 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। हालांकि विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बढ़े हुए वेतन का 11 माह का एरियर दिया जाएगा या नहीं, पर श्रमिक संगठन मानकर चल रहे हैं कि उन्हें अप्रैल 2024 से ही बढ़ा वेतन और एरियर मिलेगा। क्योंकि कोर्ट ने मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की वेतनवृद्धि की अधिसूचना के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को मामले का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि टेक्सटाइल एवं मेड अप्स उद्योग, वूवन-निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाइल फेब्रिक से बने अपेरल और फुट वियर निर्माण इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग से वेतन तय करें। प्रदेश में इन उद्योगों में करीब 4 लाख श्रमिक काम करते हैं, जिन्हें बढ़े हुए वेतन के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने नवंबर 2019 में श्रमिकों के वेतन में 25 प्रतिशत वृद्धि की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा को सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से लागू किया। श्रमिकों को अप्रैल में बढ़ा हुआ वेतन मिला था कि मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वेतनवृद्धि की अधिसूचना को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया था, जो लगातार सुनवाई के बाद 3 दिसंबर 2024 को हटा दिया गया।

संपादकीय

महाकुंभ : अब सियासी लाभ के दावे

विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर समापन हो गया। इस महाकुंभ में सरकारी दावे के मुताबिक 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के समय मची भगदड़ में 37 श्रद्धालुओं की मौत और आगजनी की आधा दर्जन दागदार घटनाओं को छोड़ दें तो इस महाविराट आयोजन की व्यवस्था को मोटे तौर पर सभी ने सराहा। अमीर गरीब, ऊंची नीची जातियों और हिंदुओं के अलावा बौद्ध, सिख और जैन धर्म के लोगों ने भी अपनी श्रद्धा के मुताबिक संगम में स्नान कर पुण्य कमाया। इस महाकुंभ की विशेषता यह रही कि इसमें तमाम इंतजाम और श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ तो थी ही, साथ में इसे धार्मिक पर्यटन, आर्थिक प्रबंधन और परोक्ष रूप से राजनीतिक निवेश का रूप भी बहुत सुनियोजित तरीके से दिया गया था। यही कारण है महाकुंभ की सफलता के बाद उन्नाव से भाजपा साक्षी महाराज ने कहा कि महाकुंभ की सफलता ने यह कर दिया है कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी। इसका सीधा अर्थ यही है कि अगर अभी चुनाव हुए तो भाजपा बंपर वोटों से जीतेगी। मसलन संगम में डुबकी लगाने वाले सभी 66 करोड़ हिंदू भाजपा के वोटर हुए तो यह संख्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को देश भर में मिले कुल 23 करोड़ वोटों से भी दोगुनी होगी। लेकिन यह कागजी गणित है और कुंभ में स्नान करने वाला हर व्यक्ति भाजपा का ही वोटर हो, यह जरूरी नहीं है। यानी कि हरेक की धार्मिक और राजनीतिक आस्था एक सी हो ये जरूरी नहीं है। और राज्यों के मामले में यह प्रकरण और भी अलग हो जाता है। महाकुंभ का भाजपा को कितना लाभ मिलेगा, मिलेगा या नहीं इस प्रश्न को अलग रखें तो भी योगी सरकार ने जिस बड़े पैमाने पर इंतजाम किए और इस में लोगों ने जिस तरह दिन रात मेहनत कर महाकुंभ को सफल बनाने में जी जान लगा दी। उनकी सराहना अवश्य की जानी चाहिए। इसी तरह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपने विभाग के कर्मचारियों की कुंभ में दी गई उनकी सेवाओं की तारीफ की। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाकुंभ की लगातार मॉनिटरिंग की। हालांकि इस समागम के समापन पर उन्होंने महाकुंभ के आलोचकों को बुरे शब्दों में लताड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि महाकुंभ कहीं कोई अव्यवस्था थी ही नहीं। जो थी, उस पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ी। अपनी तकलीफों को लोगों ने पुण्य लाभ की अपेक्षा में अनदेखा किया। महाकुंभ के अंत योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस ढंग से कुंभ के सफाई कर्मियों के साथ बैठकर भोजन किया, उन्हे बोनस घोषित किया, सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को भी पुरस्कृत किया, उसकी सराहना की जानी चाहिए। चंद खामियों के बावजूद इतना महाविराट आयोजन करना भी अपने आप में उपलब्धि है। यह विश्व इतिहास में अभूतपूर्व है। यही कारण है कि सनातनियों के इस महापर्व का सारी दुनिया ने सुखद आश्चर्य के साथ नोटिस लिया। इस मायने में यह महाकुंभ भविष्य में होने वाले आयोजनों के लिए एक मिसाल और मार्गदर्शक भी है। महापर्व के समापन के बाद इस पर राजनीति होना तय है। विपक्ष की कोशिश है कि इस आयोजन का श्रेय भाजपा को न मिले। खुद भाजपा में कुछ लोग चाहेंगे कि इसकी क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को न मिले। क्योंकि इसने योगी की दिल्ली में दावेदारी को और पुख्ता किया है। अगर योगी यूपी में तीसरी बार भाजपा को सत्ता में लौटा लाते हैं तो तय मानिए कि मोदी के बाद वो भाजपा व संघ की पहली पसंद होंगे। अब यह यूपी की जनता पर निर्भर है कि वो तीसरी बार योगी को सत्ता सौंपती है या नहीं।

नजरिया

अशोक भाटिया

लेखक मुंबई निवासी स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार में उथल-पुथल

बांग्लादेश पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। शेख हसीना की सरकार चली गई थी। उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा। फिर अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस पर आ गई। लेकिन एक बार फिर, देश में हिंसा भड़क उठी है। शेख हसीना के शासन के अंत को एक साल भी नहीं हुआ है। वहीं, बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। ये था। छात्र आंदोलन का नेतृत्व शेख हसीना की सरकार के दौरान छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने किया था। इस आंदोलन के कारण शेख हसीना की सरकार गिर गई। अब छात्र एक बार फिर यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं।

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार है, जिसमें नाहिद इस्लाम को एडवाइजरी का पद दिया गया था; लेकिन अब उन्होंने सलाहकार के रूप में पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की है। शेख हसीना की सरकार के दौरान भेदभाव विरोधी आंदोलन और हिंसक छात्र आंदोलन हुए थे। वह हसीना सरकार के पतन के मुख्य कारणों में से एक थे। छात्र आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने किया था। कार्यवाहक के रूप में पद छोड़ने के नाहिद इस्लाम के फैसले ने बांग्लादेश में यूनुस सरकार की स्थिरता के बारे में संदेह पैदा कर दिया है और अटकलें लगाई हैं कि यूनुस सरकार जल्द ही कभी भी गिर जाएगी।खबर यह भी है कि वह नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं और जल्द इसका ऐलान हो सकता है।

बीडीन्यूज डॉट 24 की रिपोर्ट के मुताबिक, नाहिद इस्लाम और सरजिस आलम इस नए दल की अगुवाई कर सकते हैं। सरजिस स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के कॉर्डिनेटर हैं। बता दें कि नाहिद इस्लाम की अगुवाई वाले छात्र आंदोलनों के बीच पिछले साल पांच अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा था और उन्होंने भारत में शरण ली थी। इसके बाद आठ अगस्त को मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में नई अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला था।

अब अगर हम बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम को देखें तो छात्र यूनुस सरकार के कुछ फैसलों से नाखुश हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर, 31 दिसंबर की शाम को, हजारों छात्र ढाका में केंद्रीय शाहिर मीनार के पास इकट्ठा हुए और वर्तमान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। छात्र संघ बांग्लादेश के निर्माण के समय 1972 में लागू संविधान को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। छात्र संघ ने भारत के संविधान को मुजीबिस्ट संविधान के रूप में वर्णित किया है। छात्रों का आरोप है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत और बांग्लादेश, जिनके कभी दोस्ताना संबंध थे, अब तनाव के बिंदु पर पहुंच गए हैं। भारत-बांग्लादेश संबंध चीन के साथ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की निकटता के कारण बिगड़ते प्रतीत होते हैं। भारत ने

1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश को मान्यता दी। भारत और बांग्लादेश दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच निरंतर दोस्ती को मनाने के लिए फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। शेख हसीना के शासनकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत थे; लेकिन उनके अपदस्थ होने के बाद, स्थिति बदल गई। शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के बाद भारत आईं। मोहम्मद यूनुस की नीतियों ने भारत के साथ संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। विश्व आर्थिक मंच पर बोलते हुए, मोहम्मद यूनुस ने चीन की प्रशंसा की और संकट के समय में बांग्लादेश को चीन के समर्थन का उल्लेख किया।

इससे पहले बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार-उज्जमान ने सभी नेताओं को चेतावनी देते हुए उन्हें आपस में नहीं उलझने को कहा था। उन्होंने कहा था कि इससे देश की संप्रभुता को खतरा हो सकता है। अगर लोग अपने मतभेदों ना भुला पाए या एक-दूसरे पर आरोप लगाना बंद ना कर पाए तो देश की संप्रभुता दांव पर लग सकती है। उन्होंने मंगलवार को पिलखाना नरसंहार की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। बाद में यह मत कहना कि मैंने आगाह नहीं किया। अगर आप अपने मतभेदों को भूलाकर साथ मिलकर काम नहीं करते हैं तो एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने पुलिस बल की अक्षमता पर भी सवाल उठाए और बताया कि कई अधिकारी डर में जी रहे हैं, क्योंकि उनके साथी या तो जेल में हैं या उन पर मुकदमे चल रहे हैं।

सेना प्रमुख ने कहा कि देश की कानून एवं व्यवस्था खराब होने के ये कुछ कारण हैं। पहला कारण है कि हम आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं। अगर आप अपने मतभेदों को नहीं भुलाते हैं तो इससे दिक्कत होगी। देश की संप्रभुता जोखिम में पड़ जाएगी। मैं चेतावनी दे रहा हूं। सभी नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं जिससे शरारती तत्वों को माहौल बिगाड़ने में फायदा हो रहा है। इस अराजक स्थिति में वे आसानी से बच रहे हैं।

लोगों को एक बड़ी चिंता ये भी है कि यूनुस के जमात-ए-इस्लामी से अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। कम से कम उनके हालिया राजनैतिक फैसलों से यही झलकता है। अंतरिम सरकार के लीडर बतौर उन्होंने इस गुट पर लगी पाबंदियां हटा दीं। बता दें कि जमात-ए-इस्लामी पर कट्टरपंथी राजनैतिक गुट है, जिसके खिलाफ खुद वहां की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए उसके चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी। पॉलिटिकल गतिविधियों के अलावा वो कोई सभा भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अंतरिम सरकार के आते ही उसपर से सारी रोकटोक खत्म हो गई।

बताया यह भी जाता है कि हेफाजत-ए-इस्लाम भी एक कट्टरपंथी संगठन है, जिससे यूनुस से रिश्ते सामने आ रहे हैं। बेहद कट्टर इस गुट की विचारधारा महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ है, यहां तक कि इसके नेता भी अपनी भारत-विरोधी सोच के लिए जाने जाते हैं। यूनुस का हाल में इन नेताओं से संपर्क बढ़ा। अगस्त 2024 में, उन्होंने इसके नेता ममनुल हक से मुलाकात की, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। वैसे ये भेंट राजनैतिक मदद जैसे मुद्दों को लेकर थी लेकिन भारत विरोधी छवि वाले लीडर से मुलाकात को लेकर भी यूनुस घिरे। सत्ता संभालने के साथ ही यूनुस ने कहा था कि जरूरी बदलावों के बाद इलेक्शन होगा। तीन महीने गुजर चुके लेकिन इसकी कोई आहट नहीं। बता दें कि बांग्लादेशी संविधान के अनुसार, संसद के खत्म होने के तीन महीनों के भीतर नई सरकार का चयन हो जाना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुआ। इसके साथ ही, अंतरिम सरकार ने कोई तारीख भी नहीं दी है कि फलां से फलां समय के बीच इलेक्शन हो सकता है। राजनैतिक माहौल में प्रेस की आजादी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे यूनुस की छवि कमजोर ही हो रही है।

मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों पर खेद व्यक्त किया था और कहा था कि 'बांग्लादेश-भारत संबंध यथासंभव मजबूत होने चाहिए'। यद्यपि भारत और बांग्लादेश का नक्शा अन्योन्याश्रित था, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी कि भारत पर संबंधों को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। दूसरी ओर, बांग्लादेश के नागरिक उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। खाद्य मुद्रास्फीति की दर 13 प्रतिशत तक पहुंच गई है और सरकार ने वैट बढ़ा दिया है। वृद्धि ने नागरिकों के लिए जीवन कठिन बना दिया है, भले ही सरकार राजस्व में 12,000 करोड़ रुपये एकत्र करने का दावा करती है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगर संबंध और बिगड़ते हैं तो इसका निर्यात प्रभावित होगा। इसका असर बांग्लादेश की जीडीपी पर पड़ेगा और फिर इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि महंगाई के साथ-साथ बेरोजगारी भी बढ़ती है। बांग्लादेश के लिए भारत के साथ बिगड़ते संबंधों की कीमत चुकाना अब आसान नहीं होगा। अगर बांग्लादेश के लोग सड़कों पर लौट आए तो यूनुस के लिए अस्थिरता के चक्र से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा।

पर्यावरण

डॉ. ललित कुमार

लेखक इन्वर्टिस विश्वविद्यालय बरेली में पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष हैं।

रेडियो के जरिए जलवायु परिवर्तन को साधने की कोशिश

यूनेस्को ने वर्ष 2011 में विश्व रेडियो दिवस को हर वर्ष 13 फरवरी को मनाने की घोषणा की। तब से लेकर आज तक फरवरी की 13 तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाने की परंपरा बन गई है। देशभर के पत्रकारिता विभाग में मीडिया की पढ़ाई कर रहे युवा पीढ़ी ने शायद ही इस श्रव्य माध्यम को कभी सुना हो। अमूमन रेडियो सुनने वालों की तादाद पिछले कुछ वर्षों में गिरावट देखी गई है, जोकि एक चिंता का विषय हो सकती है। आजादी के बाद से रेडियो को तीव्र गति वाला एक सशक्त माध्यम माना जाता था। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो को सबसे ज्यादा सुनने वाला माध्यम माना गया। रेडियो ने ग्रामीण व शहरी समाज के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। क्योंकि यह सभी वर्गों को समान रूप से सूचना देने का काम करता है।

रेडियो जहां तीन फॉर्मेट पर काम करने वाला माध्यम माना जाता है। जिनमे क्रमशः बोले जाने वाला शब्द या मानव ध्वनि, संगीत और ध्वनि प्रभाव के रूप में जनता के दिलों की धड़कन बना। रेडियो हमेशा संचार का एक ऐसा माध्यम रहा, जिसने कभी किसी धर्म संप्रदाय के ख़िलाफ़ या सूचनाओं के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि सूचना को हर वर्गों के बीच बड़ी शालनीनता के साथ प्रसारित किया। रेडियो ने देश के विकास में सूचनाओं की सीमा को समझा और सभी के साथ न्याय किया। किसी भी वर्ग को निराश न करने वाला यह माध्यम आज भी इतना प्रासंगिक है कि इसकी पहचान और इसके श्रोता रेडियो को सम्मान के साथ ही सुनना पसंद करते है।

वर्ष 2025 की थीम 'रेडियो और जलवायु परिवर्तन' को लेकर रखी गई। जहां आज हर देश और हर समुदाय को जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। लोगों को जागरूक करने के लिए रेडियो ने फिर से यह पहल की है। प्राकृतिक आपदाओं आपातकालीन समय या कर्फ्यू के समय सबसे सशक्त माध्यमों में से एक रहा है। रेडियो श्रोता इतना तो समझ ही सकते है कि रेडियो की आवाज उनके कानों में मधुर वाणी का एहसास कराती है, जो टीवी की आवाज़ से कहीं अधिक सभ्य और शालीन है। रेडियो कभी भी ऐसे प्रसारण को नहीं मानता नहीं देता, जिससे आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचे। रेडियो पर न ही कभी किसी ऐसी भ्रामक सामग्री को प्रसारित किया जाता है। रेडियो एक ऐसा ब्लाइंड माध्यम है, जो अपने श्रोताओं को, आवाज के जरिए कल्पनाओं के माध्यम से मूल्यांकन कराने में भी मदद करता है।

समय के साथ रेडियो ने अपने रूप और दायरे को पूरी तरह से बदल दिया है। कभी लकड़ी की बडे डिब्बों में सिमटा रेडियो, जो आज आपकी

जेब, घड़ी और मोबाइल सेट में समा चुका है। आज रेडियो एफएम और एएम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पॉडकास्ट, सैटेलाइट रेडियो और इंटरनेट रेडियो, जो मनोरंजन और जानकारी का एक अनगिनत खजाना है। लेकिन क्या आपको पता है शुरुआती दौर में रेडियो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना मुश्किल होता था। यह सोचने वाली बात है कि अगर उस दौर में रेडियो नहीं होता तो आप और हम कैसे एक दूसरे से जुड़ पाते। रेडियो संचार का वह माध्यम है जो अपने आप में बहुत-सी यादें समेटे हुए हैं। चाहे बचपन में रेडियो पर हर रविवार को हवा महल कार्यक्रम को सुनना, रात 9:00 बजे बिनाका गीतमाला कार्यक्रम पर अमीन सयानी की आवाज सुनने के लिए बेताब होना। यानी रेडियो उसके श्रोताओं के लिए एक हमसफर का माध्यम रहा है, जिसे कहीं भी सुना जा सकता था। रेडियो के हर वो एंकर जिन्हें कभी देखा नहीं। बस उनकी आवाज की पहचान ही श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ देती है। रेडियो दुनिया की समस्याओं से लेकर सूचनाओं को एक सूत्र में पिरोकर एक ऐसा मंच देता है, जिसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती। आज का युग भले ही मोबाइल और सोशल मीडिया का हो, लेकिन रेडियो का जादू आज भी उनके श्रोताओं पर सिर चढ़कर बोलता है।

विश्व रेडियो दिवस के मौके पर पत्रकारिता और जनसंचार संस्थान इस दिन को याद करना कहीं न कहीं रेडियो की पूरी यात्रा को और आज

के युवाओं को उसकी प्रासंगिकता को भी समझाना बेहद जरूरी है। रेडियो ट्रांसमिशन यानी सीक्रेट रेडियो ट्रांसमिशन सेट के जरिए 22 साल की एक लड़की ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी, नाम था उषा मेहता। जो एक सीक्रेट रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए गांधी, नेहरू और पटेल के अंग्रेजों छोड़ो भारत आंदोलन के आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रही थी।

वर्ष 1942 में जेल भरो आंदोलनकारियों के समर्थन में उषा मेहता मुंबई की ऊंची इमारत से गुपचुप तरीके से इस गुप्त ट्रांसमिशन के जरिए रेडियो संदेश प्रसारित करती थी, जो फिलहाल बेंगलुरु के शॉर्ट वेव रेडियो म्यूजियम में अभी रखा हुआ है। जिसे सीक्रेट कांग्रेस रेडियो कहा जाता था। उषा मेहता लकड़ी के बड़े डिब्बों को लेकर बड़ी-बड़ी इमारत से रेडियो पर प्रसारण करती थी। यह सिलसिला करीब तीन-चार महीने तक चला। आखिर में उषा मेहता को ब्रिटिश हुकूमत ने एविएशन रेडियो की मदद से पकड़ लिया गया था। भारत में रेडियो सेट को पहली बार फिलिप्स कंपनी ने बनाया और उस वक्त रेडियो रू. 300 में आते थे। उनकी कीमत आज के अनुसार, करीब रू. 32000 है। उस वक्त रेडियो काफ़ी वजनदार होते थे। यानी 27 किलो तक के रेडियो बनाए जाते थे। जिसकी कीमत रू. 4500 होती थी, जिनकी वर्तमान में कीमत करीब 8 लाख रुपए आंकी जाती है। रेडियो संचार अविष्कारदाताओं के प्रमुख वैज्ञानिक निकोला टेस्ला (1893-1895), गुल्येल्मो मारकोनी (1895-1901), और रेगिनाल्ड फसेंडेन (1906) के नाम प्रमुख है। 24 दिसंबर 1906 की शाम को अपना वायलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना। जिसे दुनिया में रेडियो प्रसारण की पहली शुरुआत मानी जाती है।

भारत में रेडियो की स्थापना 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब में हुई। वर्ष 1927 में अंग्रेजी हुकूमत ने मुंबई इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी आईबीसी की स्थापना 1936 में की थी। जिसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आजादी दिलाने में रेडियो का अहम रोल रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से रेडियो पर 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' संदेश को रेडियो पर प्रसारित किया था। रेडियो की लोकप्रियता भले ही पहले से ज्यादा ग्लोबल बन चुकी हो। लेकिन रेडियो अब हर सस्ते से सस्ते मोबाइल हैंडसेट में सुनने को मिल जाता है। रेडियो को इंटरनेट के जरिए श्रोताओं के लिए ओर भी बेहतर सूचना और मनोरंजन को अलग ढंग में प्रसारित करता है। जिसके चलते रेडियो श्रोताओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इस साल की थीम, रेडियो प्रसारण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को उजागर करना साथ ही पत्रकारिता की कवरेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना।

वैज्ञानिक चेतना और हमारा व्यवहार

अनुभव

अनिल धीमन

लेखक स्तंभकार हैं।

28 फरवरी को रमन दिवस मनाया गया। आज हम देखते हैं कि वैज्ञानिक सोच के मामले में हम आगे की जगह पीछे जा रहे हैं क्योंकि मामला वैज्ञानिक सोच-विचार के होने और उसको दैनिक व्यवहार में अपनाने का है। ये जरूरी नहीं कोई व्यक्ति पेशे से वैज्ञानिक हो लेकिन उसके चेतन और व्यहार में वैज्ञानिक सोच झलकनी चाहिए।

आजादी के 74 साल बाद भी देश में एक वर्ग ऐसा है जिन्हें लगता है कि दुनिया को कोई एक शक्ति संचालित कर रही है। बेशक हम जिस ब्रह्मांड के एक छोटे से सौर मंडल के एक तुच्छ ग्रह के प्राणी मात्र हैं और कुछ नहीं। जो कुछ भी हम है सब एक तारे के अंश है जिसे एक शक्ति कह सकते हैं क्योंकि हमारा सूरज ही सब कुछ है जो हमें ऊर्जा देता है। अगर ये सूरज कुछ घंटों के लिए बुझ जाए तो हमारी पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी और हम सब डायनासौर की तरह फॉसिल में तब्दील होने की प्रक्रिया चले जाएंगे। खैर, यह अनुमान है लेकिन उसके भी लिए 6 करोड़ वर्ष का समय लगेगा और यह तब होगा जब सूरज सुपरनोवा एक्सपोलोसन या रेड जॉइंट की स्थिति में आएगा यानी धरती का सबसे करीबी तारा हमारा सूरज मरने लगेगा। तारे जब मरते हैं तो उनका आकार कई लाख गुना बड़ा होता है। ठीक उस तरह जैसे बुझने के पहले दीये की लौ बढ़ जाती है। तारे इसी तरह मरते हैं।

1609 को वैज्ञानिक चिंतन का स्वर्ण युग माना जा सकता है। यूरोप का यह दौर चर्च की शक्ति के अधीन था। एक छोटा से साधारण सा यंत्र (टेलीस्कोप) का उपयोग करते हुए गैलीलियो गैलिली ने आकाश के चमकते ऐसे पिंडो (ग्रहों) को खोज निकाला जो धरती की तरह सूरज के चक्कर लगाते हैं। यह बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैली और इस पर बहसों का दौर शुरू हुआ। खुद एक धार्मिक गुरु (चर्च में पादरी) होने के बावजूद गैलीलिओ गैलिली ने पुरातन विचार को चुनौतियां दी। इसके परिणामस्वरूप गैलीलियो को नज़रबंद कर दिया और मरते दम तक रहना पड़ा।

बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रह , शनि का वलय (रिंग) आज से 400 वर्ष पूर्व गैलीलियो ने एक छोटे से टेलीस्कोप से खोज लिया था। उस सच को आज भी आप आकाश में देख सकते हैं और सोच सकते है कि एक धर्म का प्रचारक पादरी होकर भी वैज्ञानिक सोच कि वजह से आज दुनिया को इस रूप में बदलने कि सोच को विकसित कर गया। हालाँकि उससे पूर्व और उस दौर के भारतीय वैज्ञानिकों का भी खगोल विज्ञान कि व्याख्याओं में योगदान रहा है। 1734 देश में बने जंतरमंतर जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह कि वैज्ञानिक सोच का ही नतीजा है। जतरमंतर जयपुर के अलावा दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में स्थित हैं।

मेरा मानना है कि धार्मिक होना व्यक्तिगत मामला है। हमारा संविधान इस बात की स्वतंत्रता भी देता है कि आप किसी भी धर्म या भाषा को अपना सकते हैं। कथनी और करनी का अलग होना आपको वैज्ञानिक सोच से दूर करता है। हम सब जानते हैं अविष्कार करने के लिए संघर्ष होगा ही, कुतर्कों से भी गुजरना पड़ेगा। घर और विद्यालय के अंतर्द्वंद को वो बच्चा समझ नहीं पाता है। बच्चे को स्कूल में यह बताया जाता है कि एक खास समय में पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के एक सीध में आने से सूर्य ग्रहण होता है। वो परीक्षा में जवाब भी यही लिखता है जो पढ़ाया गया है लेकिन मान्यताएं उसके दिमाग से राहु-केतु निकलने नहीं देती है। यह असर केवल बच्चों तक नहीं सीमित है, जो शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहे हैं अधिकतर वे भी उलझे हुए हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक
उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

सचिन सिंह परिहार

लेखक व्यंग्यकार हैं।

टूटी कुर्सी और लूटी व्यवस्था

हवाई जहाज में बैठना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आम आदमी तो ट्रेन के जनरल डिब्बे में लटकते-फटकते सफर करता है, लेकिन जब कोई विशिष्ट व्यक्ति हवाई यात्रा करता है, तो मामला अलग ही रंग में रंग जाता है। और अगर वह विशिष्ट व्यक्ति सरकार के करीबी हो, तो फिर क्या कहने!

उस दिन मैं भी एक विमान में सफर कर रहा था। मेरे ठीक आगे वाली पंक्ति में 8सी सीट पर एक सज्जन बैठे थे, जिनके चेहरे पर हल्की चिंता और भारी असहजता थी। मैंने गौर किया कि उनकी सीट थोड़ी अंदर धंसी हुई थी, मानो वह खुद को बचाने के लिए जमीन में समाने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने कभी इधर-कभी उधर देखा, फिर गहरी सांस ली, और जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल मिलाया।

फोन की स्क्रीन पर चमकता था 'भानेज कॉलिंग'।

मामा और उनकी टूटी कुर्सी 'नमस्ते मामा! कहाँ हैं आप?' दूसरी ओर से आवाज़ आई।

'अरे भानेज, क्या बताऊँ! फ्लाइट में हूँ, और देखो, टूटी हुई सीट पर बैठाया है मुझे। बैठना मुश्किल हो रहा है!' मामा ने शिकायत की, मानो देश का सबसे बड़ा संकट इसी समय उन पर टूट पड़ा हो।

भानेज की आवाज़ में चिंता झलकी 'ओह! यह तो गंभीर बात है मामा! लेकिन आप चिंता न करें, विमानन मंत्रालय मेरे अधीन है। मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा।'

मामा की पीड़ा कुछ इस तरह झलकी जैसे एक दिन की तकलीफ से पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन तभी पास बैठे एक बुजुर्ग यात्री मुस्कुराते हुए बोले, 'मामा जी, कुर्सी टूटी है, लेकिन किसानों की टूटी उम्मीदों का क्या? उनकी समस्याएँ कौन सुलझाएगा?' मामा थोड़ा असहज होकर 'अरे भाईसाहब, किसानों के लिए बजट में बहुत कुछ हैज हवाई जहाज में चर्चा का क्या फायदा! लेकिन अभी बात एयरलाइन की लापरवाही की है।'

इतने में पीछे से एक युवा यात्री हंसते हुए बोला, 'वाह मामा! एक दिन की असुविधा से आप इतने परेशान हैं। लेकिन किसानों की दशकों से चली आ रही समस्याओं पर कब ध्यान देंगे?'

मामा के चेहरे पर हल्की परेशानी के बादल मंडराने लगे। वे कुछ कहते, इससे पहले ही भानेज ने गंभीर स्वर में कहा, 'मामा, मैं समझता हूँ। एयर इंडिया की यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।'

अब तक सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन तभी बगल वाले यात्री ने तंज़ कसते हुए कहा, 'भानेज जी, एयर इंडिया आपके मंत्रालय के अधीन है। अपनी ही लापरवाही पर आप क्या कहेंगे?'

विमान में हल्की हंसी गूंज उठी। मामा असहज होकर सीट एडजस्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन सीट जस की तस थी। तभी एयर होस्टेस पास आई।

'सर, हम आपकी सीट बदल सकते हैं।'

मामा ने सोचा, 'अगर सीट बदल लूंगा तो जनता को क्या संदेश जाएगा?' इसलिए उन्होंने महानता का परिचय देते हुए कहा, 'नहीं, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। उनकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। मैं इसी सीट पर सफर करूंगा।'

अब तक यात्री भी मनोरंजन का पूरा लुत्फ उठा चुके थे। किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, 'मामा जी, किसानों की समस्याएँ भी समझिए, सिर्फ अपनी कुर्सी की नहीं।'

मामा चुप हो गए। भानेज भी कुछ नहीं बोल पाए। फ्लाइट लैंड हुई। मामा उठे, कैमरे की ओर देखा, और गंभीर मुद्रा में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे 'यात्रियों की समस्याएँ हमारी प्राथमिकता हैं। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा!'

मुझे हंसी आ गई। मैंने बगल में बैठे यात्री से कहा, 'टूटी कुर्सी तो बहाना था, असली निशाना तो भानेज पर था!' यात्री मुस्कुराए और बोले, 'और जनता? वह फिर से अपनी दैनिक समस्याओं में व्यस्त हो जाएगी।'

मैंने खिड़की से बाहर झांका जहाँ एक और 'टूटी कुर्सी' किसी नए नाटक का इंतज़ार कर रही थी।

कलापक्ष

डॉ. सत्यवान सौरभ

लेखक पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो हैं।

सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े हैं कलाएं व रंगमंच

आधुनिक रंगमंच सांस्कृतिक उत्पादन के औपनिवेशिक मॉडलों और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रतिच्छेदन ने आधुनिक रंगमंच को आकार दिया है। रंगमंच सहित प्रदर्शन कलाएँ सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त साधन तथा चर्चा के लिए एक जीवंत मंच बनी हुई हैं। रंगमंच लंबे समय से भारत में जागरूकता बढ़ाने, सुधार और प्रतिरोध के लिए एक सशक्त साधन रहा है, जिसका प्रभाव राजनीतिक आंदोलनों के साथ-साथ सामाजिक संरचनाओं पर भी पड़ा है। शास्त्रीय रीति-रिवाजों से लेकर समकालीन नुक्कड़ नाटकों तक, इसने सामाजिक बदलावों को प्रतिबिंबित करने और प्रभावित करने के लिए कभी भी बदलाव करना बंद नहीं किया है। सामाजिक अन्याय को लंबे समय से रंगमंच के माध्यम से प्रकाश में लाया जाता रहा है।

जैसे-जैसे क्षेत्रीय नाट्य परम्पराएँ विकसित हुई हैं, भारत का रंगमंच और प्रदर्शन कलाएँ सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक रही हैं। न्याय को बढ़ावा देने, सत्ता का विरोध करने और सामाजिक अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रंगमंच एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। बढ़ते क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, राष्ट्र का प्रश्न और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की जटिल कथाओं ने क्षेत्रीय नाट्य परम्पराओं के विकास को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, बंगाली नाटक नील दर्पण (1860) में बताया गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान नील की खेती करने वाले किसानों का किस प्रकार शोषण किया जाता था।

आधुनिक रंगमंच सांस्कृतिक उत्पादन के औपनिवेशिक मॉडलों और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रतिच्छेदन ने आधुनिक रंगमंच को आकार दिया है। रंगमंच सहित प्रदर्शन कलाएँ सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त साधन तथा चर्चा के लिए एक जीवंत मंच बनी हुई हैं। रंगमंच लंबे समय से भारत में जागरूकता बढ़ाने, सुधार और प्रतिरोध के लिए एक सशक्त साधन रहा है, जिसका प्रभाव राजनीतिक आंदोलनों के साथ-साथ सामाजिक संरचनाओं पर भी पड़ा है। शास्त्रीय रीति-रिवाजों से लेकर समकालीन नुक्कड़ नाटकों तक, इसने सामाजिक बदलावों को प्रतिबिंबित करने और प्रभावित करने के लिए कभी भी बदलाव करना बंद नहीं किया है। सामाजिक अन्याय को लंबे समय से रंगमंच के माध्यम से प्रकाश में लाया जाता रहा है।

ब्रिटिश शासन के दौरान नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण को 1860 में बंगाली थियेटर के नील दर्पण द्वारा सार्वजनिक किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर नाटकों और लोक प्रदर्शनों के माध्यम से संगठित किया गया था। रंगमंच के माध्यम से, भारतीय जन रंगमंच संघ (इप्टा) ने 1943 में उपनिवेशवाद विरोधी भावना को बढ़ावा दिया। निम्न वर्ग के समुदाय रंगमंच के माध्यम से अपनी पहचान व्यक्त करने में सक्षम रहे हैं। दलित सशक्तिकरण और अम्बेडकरवादी दर्शन को भीम नाट्य (महाराष्ट्र) द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। रंगमंच का उपयोग भ्रष्टाचार को उजागर करने और नीतियों की आलोचना करने के लिए किया गया है।

1980 के दशक में, सफ़दर हाशमी के जन नाट्य मंच ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए जिनमें सरकारी नीतियों की आलोचना की गई; इसके कारण 1989 में उनकी हत्या कर दी गई। कानून और सामाजिक सुधार रंगमंच से प्रभावित हुए हैं। विजय तेंदुलकर की 1972 में प्रकाशित पुस्तक सखाराम बाइंडर में महिलाओं के अधिकारों और घरेलू दुर्व्यवहार के खुलासे पर चर्चा के परिणामस्वरूप सख्त सेंसरशिप कानून बनाये गये। धार्मिक और सामाजिक परंपराएँ: प्राचीन रंगमंच की मज़बूत धार्मिक और सामाजिक जड़ें थीं। कुटियाट्टम (केरल), जिसे 2001 में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई थी, अभी भी संस्कृत रंगमंच की परंपराओं को क़ायम रखे हुए है। लोक रंगमंच के माध्यम से सामाजिक टिप्पणी- वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को लोक परंपराओं में प्रतिबिंबित किया गया है।

नक्सलवादी आंदोलन के दौरान वर्ग संघर्ष को जत्रा (बंगाल) में दर्शाया गया। आधुनिक रंगमंच में मानवाधिकार, लोकतंत्र और भ्रष्टाचार नए विषय बन गए। 1950 के दशक में हबीब तनवीर के नया थिएटर ने लोक और आधुनिक विषयों को मिलाकर सामाजिक मुद्दों को चित्रित किया। राज्य हस्तक्षेप और सेंसरशिपः राजनीतिक रूप से संवेदनशील नाटकों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। विजय तेंदुलकर की 1972 की फ़िल्म घासीराम कोतवाल को जाति आधारित भ्रष्टाचार और शोषण को उजागर करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। डिजिटल प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता ने थिएटर के प्रभाव और पहुँच को बढ़ा दिया है। सामाजिक सक्रियता के लिए, यूट्यूब आधारित थिएटर समूह, जैसे जन नाट्य मंच, डिजिटल प्रदर्शनों का उपयोग करते हैं। भारत और विदेश के सरकारी और निजी स्रोतों ने स्वतंत्रता के बाद से भारतीय रंगमंच को इसके अनेक रूपों में सहयोग दिया है, लेकिन यह हमेशा विशिष्ट प्रतिभाओं द्वारा संचालित रहा है और पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित रहा है, साथ ही स्वदेशी संसाधनों की ओर भी मुड़ता रहा है। इस अवधि के दौरान विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश और गिरीश कर्नाड, चंद्रशेखर कंबार, पी लंकेश और इंदिरा पार्थसारती जैसे आधुनिकतावादी नाटककार पैदा हुए; उनके नाटकों का उपयोग और अध्ययन पूरी दुनिया में किया गया है।

इन नाटककारों ने थिएटर में आधुनिकतावादी आक्रोश पर गहन औपचारिक कठोरता और विषयगत ध्यान केंद्रित किया। पहचान का संकट और वैश्वीकरण के परिणाम उन विषयों में से हैं जिन पर युवा लेखक वर्तमान में कई स्थानों पर चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक भारतीय रंगमंच मुख्यतः तीन परंपराओं से प्रभावित हैः संस्कृत रंगमंच, लोक रंगमंच और पश्चिमी रंगमंच। वास्तव में, तीसरा वह है जिसे आज भारतीय रंगमंच की आधारशिला माना जा सकता है। हम सभी देख सकते हैं कि समय के साथ रंगमंच और प्रदर्शन कलाएँ किस प्रकार विकसित हुई हैं, उन्होंने सत्ता को चुनौती दी है, न्याय को बढ़ावा दिया है, तथा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया है। आज, पूरे देश में कई थिएटर समूह और निजी से लेकर सरकारी संस्थानों तक कई थिएटर अभिनय संस्थान हैं। अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए, उन्हें सांस्कृतिक संरक्षण, डिजिटल एकीकरण और नीति समर्थन के लिए पहल के माध्यम से अपनी स्थिति को मज़बूत करना होगा। जबकि शोषितों या आम जनता के जीवन में सामाजिक परिवर्तन लाना, नुक्कड़ नाटक आंदोलन और यात्रा के केंद्र में है।

इसे प्राप्त करने के लिए 'प्रगतिशील सामुदायिक विकास' प्रक्रिया को 'लोकप्रिय शिक्षा' के साथ संयोजित करना आवश्यक है। एक लोकप्रिय रंगमंचीय अभ्यास के रूप में, नुक्कड़ नाटक एक सहभागी प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास करते हैं जो लक्षित दर्शकों के 'सांस्कृतिक रूपों' के प्रति संवेदनशील होती है। नुक्कड़ नाटक, प्रोसेनियम थिएटर के विपरीत, वह स्थान है जहाँ अभिनेता अपनी कलात्मक और व्यावसायिक रुचियों को अपनी राजनीतिक और सामाजिक मान्यताओं के साथ जोड़ते हैं। हालाँकि, इसकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने और समाज पर प्रभाव डालने के लिए दीर्घकालिक विकासात्मक योजना को नाट्य प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह लक्ष्य नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समुदाय को जानने, लोगों की चिंताओं के मुद्दों को पहचानने, मनोरंजन और सामुदायिक अभिव्यक्ति को संयोजित करने, दर्शकों की भागीदारी को आमंत्रित करने और कार्यवाही के लिए आह्वान करने से प्राप्त किया जा सकता है।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

युवाओं के प्रति भाजपा का विश्वास सुखद अनुभूति का कारक

इसमें दो मत नहीं कि वर्तमान दौर में विशेष कर नई पीढ़ी का रझान सक्रिय राजनीति के प्रति निरंतर बढ़ रहा है। वैसे भी निरंतर परिवर्तित दौर में ऐसा समझा जाता है कि पूर्व की तुलना में आजकल के नौनिहालों की सामान्य समझ एवं बुद्धि काफी हद कुशाग्र है। इसके चलते किशोर एवं युवा पीढ़ी भी निकट भविष्य में और अधिक प्रतिभा संपन्न होगी। अब वह समय नहीं रहा कि उम्र के आधार पर वरिष्ठता ही राजनीतिक योग्यता का निर्धारण करती रही हो। निश्चित ही नए दौर में देश प्रदेश की राजनीति में युवाओं की सक्रिय भागीदारी अब समय की मांग बन गई है। इस संदर्भ में विशेष रूप से भाजपा की राजनीतिक रणनीति की सराहना करनी चाहिए।

यूं भी प्रगति के पैमानों का निर्धारण करने और उसे क्रिया रूप देने में जितने उत्साही युवा हो सकते हैं, उतनी अपेक्षा पुरानी पीढ़ी से तो नहीं की जा सकती। हालांकि उम्र की वरिष्ठता का भी अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन अनेक अवसरों पर ऐसा होता है कि देश प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु कहीं-कहीं अनुभव से ज्यादा वर्तमान की समझ भी बहुत अधिक मायने रखती है। यह निश्चित है कि पुरातन पंथी विचारधारा के चलते देश प्रदेश के प्रगति रथ को तीव्र गति प्रदान नहीं की जा सकती। दरअसल समय की धारा के अनुरूप अपनी विचारधारा को डालकर थी वर्तमान दौर में राजनीति के मूलभूत उद्देश्यों को पाया जा सकता है। एक प्रकार से अनुभव के साथ-साथ वर्तमान परिस्थितियों का ज्ञान भी बहुत मायने रखता है।

इस संदर्भ में भाजपा ने अपने शासनकाल में अनेक अवसरों पर चौंकाने वाले निर्णय लेकर जमीनी कार्यकर्ता तथा नेताओं को उत्साह से लबरेज कर दिया है। कल तक यह समझा जाता था कि पारिवारिक दृष्टि से बिना किसी ठोस राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेतृत्व की कमान हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन बीते समय में भाजपा शासित राज्यों में द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नेतृत्व की कमान सौंप कर भाजपा ने वंशवाद के दंश का काफी हद तक समुचित उपचार कर दिया था। हाल ही में नई दिल्ली की कमान पहली बार की विधायक को सौंपा जाना भी इस बात का द्योतक है कि समर्पित कार्यकर्ताओं के कार्य का भाजपा द्वारा समुचित संज्ञान लिया जाता है।

वैसे तो यह भाजपा की अंदरुनी रीति नीति का मुद्दा है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव देश प्रदेश की राजनीति पर पड़े बिना नहीं रहेंगे। वर्तमान दौर में अधिकांश प्रतिपक्षी दलों पर व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक नियंत्रण है। अधिकांश दलों में विचारधारा से अधिक व्यक्तिगत मनमर्जी का बोलबाला है। अपनों को उपकृत करते हुए अपने-अपने गुट एवं समूह को ताकतवर बनाने के निरंतर प्रयास होते रहा करते हैं। अधिकांश प्रतिपक्षी राजनीतिक नेतृत्व पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते राजनीति के मैदान में डटे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जनाधार रहित नेताओं की भी भरमार है। एक प्रकार से इस वर्ग के पास अपने दल की राजनीति का एक अलग ही रिमोट कंट्रोल हुआ करता है।

निश्चित ही भाजपा को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उसने अपनी कार्य पद्धति से देश- प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की है। आज स्थिति यह है कि अन्य दलों की अपेक्षा भाजपा के पास निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता तथा जनसेवा की भावना से ओतप्रोत छोटे-बड़े नेताओं की एक बड़ी फौज है। हर कोई इस विश्वास से भरा हुआ है कि दल के प्रति उसकी निष्ठा और समर्पण की भावना उसे बहुत आगे तक ले जा सकती है। क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वह अपना काम कर रहे हैं, तो दल द्वारा उसका संज्ञान भी लिया जाता है। यही कारण है कि भाजपा लगभग शून्य से शिखर तक का सफर कर सकी है।

हालांकि कई मुद्दों पर भाजपा को घेरा जा सकता है, कमियां निकाली जा सकती है, सत्ता संस्कृति को आत्मसात करने का आरोप भी लगाया जा सकता है, लेकिन यह भी सच है कि बाकी की तुलना में भाजपा की बात ही कुछ और है। वैसे यह विश्वास केवल कार्यकर्ता को ही नहीं है, अपितु आम नागरिक भी भलीभांति जानने लगे हैं कि भाजपा के राज में उनका कभी सामंतशाही से पाला नहीं पड़ा। यह खानदान की नहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यही बात इसे औरों से अलग करती है। राजनीति का मैदान हर किसी के लिए खुला है। लेकिन जिनके अंतर्मन में दृढ़ता होती है और नीति तथा सिद्धांतों के प्रति समर्पण की भावना होती है, उनके लिए भाजपा ही वह विकल्प है जहां संकल्प पूरे हो सकते हैं।

वर्तमान में देश और अनेक प्रदेशों का नेतृत्व वह शख्सियत कर रही है - जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी राजनीतिक नहीं रही। एक प्रकार से सभी ने साधारण कार्यकर्ता के रूप में ही राजनीतिक सफर पूर्ण किया। परिणामस्वरुप सिद्धि (सत्ता) प्राप्त होने पर योग्यता के अनुसार ही सभी के हिस्से में अपना-अपना काम आया। अब यह अलग बात है कि भाजपा के विरोधी भाजपा का विरोध तो करेंगे ही। उनका ऐसा विरोध करना ही उन्हें राजनीतिक दृष्टि से मैदान में बनाए रखता है। लेकिन आम नागरिक तब और अब में अंतर महसूस करने लगे हैं। यही कारण है कि भाजपा की प्रभावशीलता में निरंतर वृद्धि होने लगी है। जबकि प्रतिपक्षी दल सही तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन भी नहीं कर पा रहे हैं।

आर्थिकी

सचिन श्रीवास्तव

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का संकल्प

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय गहरे संकट में है। सरकार के नीति-निर्माण में असंतुलन, कर्ज का बढ़ता बोझ और सरकारी संरक्षित पूंजीवाद के कारण प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। 80 प्रतिशत से अधिक जीडीपी के बराबर कर्ज और नीति निर्माण में बड़े कॉरपोरेट समूहों की बढ़ती पकड़ ने देश की आर्थिक संप्रभुता को खतरे में डाल दिया है।

सरकार एक ओर निजीकरण और विनिवेश के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों को बेचना चाहती है, जबकि दूसरी ओर कृषि जैसे बुनियादी क्षेत्रों को बड़े औद्योगिक घरानों के हवाले करने की कोशिश कर रही है। यह नीतियाँ न केवल आम जनता के लिए आर्थिक असुरक्षा पैदा कर रही हैं, बल्कि देश की प्रतिस्पर्धी क्षमता को भी कमजोर कर रही हैं।

स्टेटिस्टा के अनुसार, भारत का राष्ट्रीय कर्ज 2020 में 88.43 प्रतिशत जीडीपी तक पहुंच गया था, जो अब भी 80 प्रतिशत से अधिक बना हुआ है। सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि अर्थव्यवस्था सुधार की ओर बढ़ रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकारी नीतियाँ कुछ विशेष औद्योगिक समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं, न कि आम जनता या लघु-मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के हित में।

सरकारी बैंक और कंपनियाँ घाटे में बताकर बेची जा रही हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाले उद्योगपतियों को सस्ते ऋण और टैक्स में छूट दी जा रही है। रेलवे, तेल कंपनियाँ, टेलीकॉम और एयरपोर्ट जैसे बुनियादी ढांचे को कुछ खास समूहों के हाथों बेचा जा रहा है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है। छोटे व्यापारियों और किसानों को बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया, जबकि बड़े उद्योगपतियों को अरबों की टैक्स रियायतें दी जा रही हैं।

सरकार बार-बार कहती है कि सार्वजनिक उपक्रम घाटे में हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? बीपीसीएल, एलआईसी, रेलवे, सेल और अन्य कंपनियों को या तो बेचा जा रहा है या उनके संसाधन निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। सरकारी संपत्तियों की बिक्री से जो पैसा आ रहा है, वह मौजूदा कर्ज चुकाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि नए कॉर्पोरेट टैक्स छूट और सरकारी खर्च बढ़ाने में इस्तेमाल हो रहा है। बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है, क्योंकि सरकारी संरक्षण प्राप्त निजी कंपनियाँ मनमाने दाम वसूल रही हैं। सवाल वही है कि यह निजीकरण की नीति है या बस बड़े कॉरपोरेट समूहों को फायदा पहुँचाने का तरीका?

तीन कृषि कानूनों को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश सरकार की नवउदारवादी सोच और पूंजीपतियों की लॉबी का स्पष्ट प्रमाण थी। ये कानून किसान आंदोलन के दबाव में वापस लिए गए, लेकिन सरकार अब भी कृषि सेक्टर में बड़े उद्योगपतियों को प्रवेश दिलाने की कोशिश कर रही है। एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दी जा रही, ताकि किसान मजबूरी में निजी कंपनियों को अपनी उपज बेचें। कृषि को ठेकेदारी खेती के हवाले करने की योजनाएँ अब भी जारी हैं, जिससे छोटे किसान बिचौलियों और बड़ी कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। सरकार ने एफसीआई का बजट लगातार घटाया है, जिससे सरकारी खरीद कमजोर हुई और किसान खुले बाजार में जाने को मजबूर हुए।

किसान विरोधी नीतियाँ क्यों ख़तरनाक हैं?

1. खाद्य सुरक्षा पर खतरा: अगर कृषि उत्पादन पूरी तरह बाजार के हाथ में आ गया, तो खाद्य पदार्थों की कीमतें निजी कंपनियाँ तय करेंगी, जिससे गरीबों के लिए अनाज महंगा हो जाएगा।

2. छोटे किसानों की बर्बादी: भारत में 86 प्रतिशत से अधिक किसान लघु या सीमांत श्रेणी के हैं। बड़े कॉरपोरेट के साथ प्रतिस्पर्धा में वे टिक नहीं पाएंगे।

3. भूमि अधिग्रहण और विस्थापन: कॉरपोरेट खेती के बढ़ने से गाँवों में जमीनें उद्योगपतियों के हाथों में जाएँगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी।

अगर सरकार सच में किसानों का भला चाहती है, तो उसे एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी होगी। एफसीआई को मजबूत करना होगा, ताकि सरकारी खरीद में कोई गिरावट न हो। कृषि आधारित छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, जिससे किसान आत्मनिर्भर बनें।

प्रतिस्पर्धी बाजार को कमजोर करने की साजिश

सच्चे प्रतिस्पर्धी बाजार का अर्थ है कि कोई भी नया व्यवसायी बिना किसी भेदभाव के बाजार में प्रवेश कर सके और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले। लेकिन भारत में सरकार खुद ही कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को बाजार पर कब्जा करने में मदद कर रही है। टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ दो-तीन कंपनियाँ ही बची हैं, क्योंकि अन्य कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया। एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे, बिजली उत्पादन और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में एकाधिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। बैंकों से कर्ज माफ़ी और टैक्स छूट केवल कुछ बड़े व्यापारिक समूहों को दी जाती है, जबकि छोटे व्यापारियों को लोन भी नहीं मिलता।

इसका खतरा क्या है?

1. महँगाई बढ़ेगी, क्योंकि कम प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियाँ मनमाने दाम वसूलेंगी।

2. नए बिज़नेस शुरू करना मुश्किल होगा, क्योंकि नए व्यवसायियों को बड़े कॉरपोरेट के साथ मुकाबला करना असंभव होगा।

3. रोजगार कम होंगे, क्योंकि बड़े औद्योगिक समूह मशीनों और स्वचालन (ऑटोमेशन) पर निर्भर रहेंगे, जिससे नौकरियाँ घटेंगी।

सरकार अगर सच में मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धा चाहती है, तो उसे छोटे और मध्यम व्यापारियों को भी समान अवसर देने होंगे। एकाधिकारवाद को खत्म करने के लिए नियम और कानून सख्त करने होंगे। सरकारी बैंकों को सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए इस्तेमाल करने की नीति बंद करनी होगी।

भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, लेकिन इस संकट का कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकारी नीतियाँ और कॉरपोरेट संरक्षणवाद है। सरकार जिन सुधारों की बात कर रही है, वे वास्तव में सिर्फ कुछ गिने-चुने उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं। निजीकरण का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सार्वजनिक संसाधनों की लूट है। कृषि क्षेत्र में बड़े कॉरपोरेट्स की घुसपैठ को रोका जाना चाहिए, ताकि किसान बिचौलियों का शिकार न बनें। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बड़े उद्योगपतियों को मिलने वाली सरकारी रियायतों को खत्म किया जाना चाहिए।

आज सवाल यह नहीं है कि भारत आर्थिक संकट से बाहर कैसे निकलेगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या सरकार सच में आम जनता की भलाई चाहती है, या सिर्फ अपने प्रिय उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाना चाहती है?

स्कॉर्पियो से टकराकर बाइक सवार किसान की मौत

बैतूल। गुरुवार-शुक्रवार की रात बैतूल में गाड़ाघाट तिराहे के पास एक सड़क हादसे में 35 वर्षीय किसान मौत हो गई। वह अपनी बाइक की मरम्मत करवाकर लौट रहा था। इस दौरान उनकी बाइक एक स्कॉर्पियो से टकरा गई। घटना के बाद उन्हें प्राइवेट एंबुलेंस से बैतूल जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आशंका है कि वह शराब के नशे में वाहन से टकरा गया। मृतक आमला जमदेही का निवासी था। वह खेती के उपकरण खरीदकर अपनी बहन के घर झगडिया जा रहे थे। अस्पताल पुलिस चौकी के हेड कॉन्स्टेबल उमाकांत मिश्रा ने मृतक की जेब से बैतूल ऑटो मोबाइल्स वर्कशॉप का बिल और 11 हजार 270 कैश बरामद किए। इसी आधार पर मृतक की पहचान की गई। परिजनों को रात में ही सूचना दी गई। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्ट्म के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिवार में एक बेटी है।

वन्य जीवों का करंट से शिकार, 72 किलो जंगली सुअर का मांस जब्त, तीन गिरफ्तार

बैतूल। वन विभाग ने अवैध शिकार के मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम सावलीगढ़ रेंज के चुनाखापा गांव में यह कार्रवाही की है। आरोपी मंगलू, झिल्लू और रामकिशन से 72 किलोग्राम जंगली सूअर का मांस बरामद हुआ है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने जंगली सूअर को पहले करंट लगाकर मारा। फिर कुल्हाड़ी से काटकर मांस निकाला। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोपियों से मारपीट का आरोप लगाया। पूर्व जनपद सदस्य डोमा सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने चिचोली स्थित वन कार्यालय में प्रदर्शन किया। वन विभाग ने आरोपियों को उनके परिजनों से मिलने की अनुमति दी। डोमा सिंह का कहना है कि जंगली जानवर किसानों की फसलें खराब करते हैं। इसलिए आरोपियों ने शिकार किया। हालांकि, वन विभाग के सूत्रों के अनुसार आरोपी मांस बेचने की योजना बना रहे थे। आरोपियों को बैतूल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

बाइक भिड़ंत में पति की मौत, पत्नी- बेटा और शिक्षक घायल

बैतूल। छिंदवाडा नेशनल हाईवे पर गुरुवार को बरखेड पंखा के पास दो बाइक की भिडंत हो गई। घटना में एक ग्रामीण की मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी, बेटा और दूसरी बाइक पर सवार शिक्षक गंभीर घायल हो गए। घायल में 5 साल का बालक भी शामिल है। सिलादेही निवासी राजेश देशमुख (40) पत्नी छाया और पुत्र अंश को लेकर बाइक से मुलताई से गांव जा रहे थे। वहीं ग्राम सावरी के स्कूल में पदस्थ शिक्षक केवल पवार निवासी कामथ बाइक से स्कूल से वापस घर लौट रहे थे। बरखेड पंखा के पास राजेश और केवल की बाइक में जोरदार भिडंत हो गई। जिससे सभी हाईवे पर गिर गए। राजेश देशमुख को सिर में गंभीर चोट आई। वहीं छाया और अंश को पैर में चोट आई। राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और राजेश, छाया और अंश को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने राजेश देशमुख को मृत घोषित कर दिया। शिक्षक केवल को नगर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। केवल के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है। केवल को परिजन प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर के अस्पताल लेकर गए हैं।

आदिमरंग नाट्य महोत्सव में सुखिया और सल्तनत ने किया दर्शकों को लोटपोट

बैतूल। नाट्य संस्था आदिम कल्चरल एंड वेलफेयर सोसायटी और ओन स्टेज ट्रस्ट आगरा द्वारा जिला प्रशासन बैतूल के सहयोग से शहीद भवन बैतूल में शुक्रवार को एक दिवसीय आदिमरंग नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस नाट्य महोत्सव में शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान दर्पण रंग समिति बरही जिला कटनी से दुर्गेश सोनी के निर्देशन में रंग संगीत की प्रस्तुति दी गई। महोत्सव की पहली

नाट्य प्रस्तुति संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से प्रस्तुत एवं राकेश वरवड़े और कलीम जफर के निर्देशन में निर्देशित नाटक सुखिया मर गया भूख से की दी गई। इस नाट्य महोत्सव में दूसरी प्रस्तुति दर्पण रंग समिति बरही जिला कटनी से दुर्गेश सोनी के निर्देशन में निर्देशित सल्तनत नाटक की प्रस्तुति दी गई। सशक्त अभिनय और निर्देशन से सजी इन नाट्य प्रस्तुतियों को देख दर्शक उत्साहित हुए और ऐसे उत्सव आगे भी आयोजित करने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है आदिम ग्रुप जिले में लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करते आ रहा है,। जिससे जिले में रंगमंचीय विकास के साथ शहर की प्रतिभाओं को सशक्त बनाया जा सके। इसी क्रम में संस्था ने आदिमरंग नाट्य महोत्सव का आयोजन किया है। इससे पूर्व संस्था ने वर्ष 2022 में तीन दिवसीय गंजन सिंह कोरकू महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि से कृषक जगदीश के जीवन में आई खुशहाली

बैतूल। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की उन्नति के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी इन योजनाओं में से एक है। बैतूल मुख्यालय के विनोबा नगर निवासी कृषक जगदीश परिहार ने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत उन्हें वर्ष में 6 हजार की राशि तीन किस्तों में मिलती है। विगत दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा योजना के तहत तीसरी किस्त के रूप में 2 हजार की राशि उनके खाते में अंतरित की है। इस राशि से उन्हें खेती-बाड़ी के कार्यों में आर्थिक मदद के साथ ही बीज, खाद एवं दवाइयों के खर्चे में काफी सहायता मिलती है। कृषक जगदीश ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण का ऐसा मजबूत आधार स्तंभ मिला है, जिससे न केवल उनके परिवारों में समृद्धि आई है, अपितु कृषि क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव हुए हैं।

राशन पर्ची नहीं बनने के कारण परेशान हो रहे हितग्राही, पोर्टल पर दिख रहा आवंटन फुल

● नाम जुड़ने के बाद भी राशन से वंचित हितग्राही

बैतूल। ई-पीडीएस पोर्टल पांच माह से बंद है। जिस कारण नवीन पात्रता पर्ची जारी नहीं हो रही है और हितग्राहियों को खाद्यान्न के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जबकि खाद्य विभाग ने शासन के निर्देश पर नए लोगों के नाम प्राथमिकता परिवारों की सूची में जोड़ दिए हैं। विभाग की मानें तो पोर्टल पर आवंटन फुल होने का मैसेज आ रहा है। इस वजह से नई पात्रता पर्ची जारी नहीं हो रही है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले परिवारों की संख्या 3 लाख 9 हजार है। जबकि प्राथमिक परिवार के सदस्यों की संख्या 12 लाख 92 हजार से ज्यादा है। वहीं शासन ने प्राथमिक परिवारों में अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया था। जिसके बाद नए प्राथमिक परिवारों को जोड़ा गया, जिससे प्राथमिक परिवारों की संख्या बढ़ गई, जो नए प्राथमिक परिवारों को जोड़ तो गया है उनकी नवीन पात्रता पर्ची पोर्टल बंद होने के कारण जनरेट नहीं हो रही है। इस वजह से पोर्टल पर नाम जुडने के बाद भी खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है।

हितग्राहियों को ई-केवायसी करना आवश्यक- ई-केवायसी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को मार्च माह के बाद राशन मिलना बंद हो सकता है। सरकार ने सभी

उपभोक्ताओं की ई-केवायसी करना अनिवार्य किया है। जिसके बाद बैतूल जिले में 3 लाख 10 हजार से अधिक परिवारों के 12.75 लाख सदस्यों की ईकेवायी कराई जा रही है। अभी तक 10 लाख से अधिक सदस्यों की ईकेवायसी हो चुकी हैं। शेष सदस्यों की ईकेवायसी काम चल रहा है। प्रदेश स्तर पर बैतूल जिले की स्थिति ईकेवायसी के मामले में बेहतर बताई जाती है।

पोर्टल पर आ रहा आवंटन फुल होने का मैसेज- बैतूल जिले में ई-पीडीएस के पोर्टल में आवंटन फुल होने का मैसेज आने के कारण पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हो रही है। जिसके कारण हितग्राहियों को खाद्यान्न आवंटित करने की समस्या हो गई है। बताया गया कि जिले की आबादी के करीब 75 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है। इस स्थिति ने जिले में गरीबों की संख्या को बढ़ा दिया है। कुल आबादी का 75 प्रतिशत लोग सरकारी खाद्यान्न पर निर्भर है। ऐसे में नए नाम पोर्टल में जोडने की वजह से पोर्टल में आवंटन ही फुल हो गया। जिसके कारण पोर्टल को बंद करना पड़ा है।

पर्ची नहीं बनने से नहीं मिल रहा खाद्यान्न - प्राथमिक परिवारों की श्रेणी में नाम जोड़ा था। उसके बाद 1402 परिवारों को शामिल किया गया है। इन परिवारों में 5 हजार से अधिक सदस्य होंगे, लेकिन पात्रता पर्ची नहीं मिलने की वजह से उक्त परिवारों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। बताया गया कि उक्त परिवार खाद्यान्न नहीं मिलने से नाराज है और विभाग के लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा पोर्टल शुरू होने के बाद ही पात्रता पर्ची जारी किए जाने की बात कहीं जा रही है।

इनका कहना है -

चार-पांच महीने से ई-पीडीएस पोर्टल बंद पड़ा है। इस वजह से नवीन पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हो रही है। पर्ची नही बनने के कारण कई परिवारों को खाद्यान्न का वितरण नहीं हो सका है। ऐसे परिवारों की संख्या देखकर ही बता पाऊंगा ।

- केके तेकाम,
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी बैतूल

खाटू श्याम जी के भजन में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु

शिवम सेवा समिति ने किया स्कूल समिति का सम्मान

बैतूल। पिछले 16 वर्षों से शिवम सेवा समिति, कमानी गेट के पास न्यू बैतूल हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान पर सार्वजनिक भण्डारा करती आ रही है। जिसमें हर वर्ष हजारों श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। इस वर्ष भी यह आयोजन समिति द्वारा इसी ग्राऊंड पर करवाया गया। भण्डारे के समापन अवसर पर खाटू श्याम जी की भजन संध्या का आयोजन किया गया था जिसमें नागपुर के हर्ष शर्मा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शिवम सेवा समिति के सुनील गुड्डू शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर, आरडी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती ऋचु खण्डेलवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष सुधाकर पंवार, पूर्व जिलाध्यक्ष बबला शुक्ला, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, पार्षद रेखा शर्मा, प्रमुख व्यवसायी एवं समाजसेवी नवीन तातेड़ मौजूद थे। शिवम सेवा समिति के रक्कू शर्मा ने बताया कि शिवम सेवा समिति द्वारा 16 वर्ष से न्यू बैतूल हाईस्कूल ग्राऊंड पर भण्डारे का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में ग्राऊंड निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए न्यू बैतूल हाईस्कूल एसोसिएशन समिति की ओर से नवनीत गर्ग का सम्मान किया गया। समिति के पम्मू शर्मा ने बताया कि भण्डारे में हर वर्ष पेयजल व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग देने वाले जित्तू आर्य एवं उनके सहयोगियों का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। इसी तरह से भण्डारा स्थल पर सफाई व्यवस्था में सहयोगी नपा के स्वच्छता निरीक्षक संतोष धनेलिया का भी सम्मान किया गया। इसके अलावा भण्डारे के दौरान जिन्होंने रक्तदान किया था उन सभी रक्तदाताओं का सम्मान किया गया।

गोवंश की तस्करी का बड़ा रैकेट बेनकाब, उत्तर प्रदेश के तस्कर गिरफ्तार, दो ट्रकों को पकड़ा

राष्ट्रीय हिंदू सेना की टीम ने हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में किया पीछा, हाईवे पर घेराबंदी कर कोसमी के पास रोका

बैतूल। नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब राष्ट्रीय हिंदू सेना और पुलिस ने गोवंश से भरे दो ट्रकों का पीछा कर तस्करों को पकड़ लिया। हाईवे पर जाम लगाकर तस्करों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रक चालकों ने बचने के लिए ट्रक को अचानक दूसरी सडक़ पर मोड़ दिया और भागने लगे, पर राष्ट्रीय हिंदू सेना और पुलिस की मुस्तैदी से यह खेल ज्यादा देर नहीं चला। करीब 1 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद कोसमी डेम के पास दोनों ट्रकों को रोक लिया गया। जब ट्रकों के अंदर का नजारा देखा गया, तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। 38 गोवंश को ठूंस-ठूंस कर बांधा गया था, दो की दम घुटने से मौत हो गई थी। ये सभी गोवंश महाराष्ट्र के अमरावती स्थित कत्लखाने ले जाए जा रहे थे। राष्ट्रीय हिंदू सेना के प्रदेश संयोजक पवन मालवीय को शाम करीब 5 बजे इस तस्करी की सूचना मिली। उन्होंने तुरंत संगठन के पदाधिकारियों को सतर्क किया और पुलिस चौकी प्रभारी नरेंद्र कुमार उइके

को जानकारी दी। इसके बाद हाईवे पर पुलिस और हिंदू सेना की संयुक्त टीम तैनात हो गई। जैसे ही ट्रक वहां पहुंचा, पुलिस और हिंदू सेना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तस्कर भागने लगे। करीब 1 किलोमीटर तक पीछा कर ट्रक को पकड़ा गया। जब ट्रक के अंदर देखा गया, तो वहां रस्सियों से जकड़े गोवंश दर्दनाक हालत में मिले। राष्ट्रीय हिंदू सेना के खुफिया तंत्र और पुलिस की सतर्कता से तस्करी को रोकने में सफलता मिली है। विभाग अध्यक्ष दीपक कोसे ने बताया एक और ट्रक क्रमांक एमपी.06.एचसी.6145 सफेद कलर ट्रक में गोवंश तस्करी की सूचना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय को मिली थी। हमने तुरंत बैतूल बाजार पुलिस को जानकारी दी। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने बैतूल बाजार के पास ट्रक को रोका, लेकिन दो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। हम लगातार प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

ग्राम बेहड़ीढ़ाना में कुष्ठ विकृति एवं बचाव शिविर आयोजित

बैतूल। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 28 फरवरी को पीओडी शिविर का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोड़ाडोंगरी के बेहड़ीढ़ाना में किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रविकांत उइके ने बताया कि शिविर में 12 मरीजों को जल-तेल उपचार से हाथ एवं पैर की देखभाल करना सिखाया गया। 7 मरीजों को एमसीआर चप्पल दी गई। कुष्ठ विकृति से बचाव के लिए हाथ-पैरों को सुरक्षित एवं नरम रखना तथा देखभाल करना सिखाया गया।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बैतूल के कोरकू नृत्य ने बिखेरी संस्कृति की छटा, विदेशी भी थिरके

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्वागत में कोरकू कलाकारों ने पेश की अद्भुत प्रस्तुति

बैतूल। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में बैतूल जिले के कोरकू कलाकारों ने अपनी पारंपरिक लोकसंस्कृति का बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में कोरकू समुदाय के कलाकारों ने मंच पर शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर अन्य जिलों के कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिससे मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर पहचान मिली। 24 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे, तब उनकी स्वागत रैली में बैतूल जिले के कोरकू समुदाय के कलाकारों ने पारंपरिक लोकनृत्य गडली सुसुन के जरिए भव्य स्वागत किया। इस अद्भुत नृत्य ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। 25 फरवरी को जब गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए, तब भी कोरकू कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य के माध्यम से उनका स्वागत किया।

जनजातीय संग्रहालय भोपाल के निदेशक डॉ. धर्मेन्द्र पारे ने कोरकू जनजातीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्कृति संरक्षण को लेकर

हर संभव प्रयास किए जाएंगे और कोरकू समुदाय की सांस्कृतिक टीम का यह योगदान अत्यंत सराहनीय है।

बैतूल जिले की कोरकू संस्कृति लोकनृत्य टीम का नेतृत्व महादेव बारस्कर बेठे ने किया। उन्होंने भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में अपनी टीम के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कोरकू संस्कृति को संरक्षित और प्रचारित करने के उनके प्रयासों की खूब सराहना हुई। गडली सुसुन नृत्य विशेषज्ञ महादेव बारस्कर बेठे को समाज में उनके योगदान के लिए शुभकामनाएं दी गईं। रैली के दौरान सरदार गंजनसिंह कोरकू और उनकी गडली सुसुन सांस्कृतिक नृत्य टीम ने अपने पारंपरिक लोकनृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विदेशी मेहमानों और बड़े उद्योगपतियों ने भी इस लोकनृत्य का आनंद लिया और कलाकारों के साथ झूमते नजर आए। यह प्रदर्शन कोरकू संस्कृति के गौरव को बढ़ाने वाला था, मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को भी प्रदर्शित करने वाला रहा।

बैतूल का बेटा फाल्गुन बना मध्यप्रदेश का टॉपर

नेशनल स्टेंडर्ड एग्जामिन इन केमेस्ट्री एंड फिजिक्स में पाई सफलता

बैतूल। जिले का नाम देश और प्रदेश स्तर पर रोशन करने वाले जिले के होनहार विद्यार्थियों में फाल्गुन राठौर का नाम भी जुड़ गया है। श्री अग्रसेन महाराज विद्यालय गंज में 12 वी क्लास के छात्र फाल्गुन पिता ओम प्रकाश राठौर ने नेशनल स्टेंडर्ड एग्जामिन इन केमेस्ट्री एंड फिजिक्स परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता, स्कूल और जिले का गौरवांवित किया शाला के डायरेक्टर रिशांक राठौर ने बताया कि,नेशनल स्टेंडर्ड एग्जामिन इन केमेस्ट्री एंड फिजिक्स (एनएसईपी, तथा एनएसईसी) परीक्षा में मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वाले मात्र कुछ छात्र ही सफल हो सके हैं, जिनमे फाल्गुन ने पूरे प्रदेश में टॉपर में रहा। फाल्गुन के क्वालिफाइड होने के बाद उन्हें देश विदेश के

प्रसिद्ध और नामी गिरामी कालेजों में प्रवेश को लेकर प्राथमिकता मिलेगी एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के क्षेत्र में अवसर भी प्राप्त होंगे। फाल्गुन की इस उपलब्धि पर स्कूल संचालक अनिल राठौर, प्राचार्य सुरेश चढोकार सहित शाला के समस्त शिक्षक , शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों ने फाल्गुन को बधाई प्रेषित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

कक्षा 12वीं के 14 हजार 336 विद्यार्थियों ने दी अंग्रेजी विषय की परीक्षा

सीएम राइज कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल बाजार में 1 नकल प्रकरण किया पंजीबद्ध

बैतूल। हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा अंतर्गत शुक्रवार को जिले के 110 परीक्षा केंद्रों पर अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र में 14 हजार 728 परीक्षार्थियों को सम्मिलित होना था जिनमें से 392 परीक्षार्थियों के अनुपस्थित रहने से 14 हजार 336 परीक्षार्थी, परीक्षा में सम्मिलित हुए। इसके अलावा शुक्रवार को कक्षा 10वी के अंतर्गत उर्दू विषय का प्रश्नपत्र भी हुआ, जिसमें 28 दर्ज में से 27 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। उन्होंने बताया कि उडन् दस्ता द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं की परीक्षा में औचक निरीक्षण के दौरान सीएम राइज कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल बाजार में 1 नकल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आज शनिवार 1 मार्च को हाई स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 10वीं के अंतर्गत एनएसक्यूएफ का प्रश्न पत्र आयोजित होगा। व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रश्न पत्र 44 केंद्रों पर होगा।

परीक्षा केंद्रों पर उड़न दस्तों की पैनीनजर- जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में विभिन्न स्तरों पर बनाए गए उडन् दस्तों द्वारा सघनता से प्रश्न पत्र के दौरान 71 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। संभाग, जिला एवं विकासखंड स्तरीय दलों द्वारा 45 तथा राजस्व एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा 26 केंद्रों का निरीक्षण इस दौरान किया गया। जिला स्तरीय दल द्वारा सीएम राइज कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल बाजार में स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए परीक्षा केन्द्र पर 01 नकल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा गठित उडन् दस्ते द्वारा भी जिले के 04 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। संभागीय दल में उप संचालक श्रीमती ज्योति प्रहलादी, उप संचालक निर्मल केलिब, सहायक संचालक श्रीमती इंदुबाला बचले एवं प्राचार्य सुदीप गौर सम्मिलित रहे। इनके द्वारा जिले के 04 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण के पश्चात परीक्षा व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर करते हुए केंद्र अध्यक्षों को जरूरी दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए।

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने की सौजन्य भेंट

भोपाल (नप्र)। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर ने नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में सौजन्य भेंट की। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु विभाग में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी से केन्द्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को अवगत कराया।

प्रदेश में बनेगी साइंस सिटी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में साइंस सिटी विकसित की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार विचार कर रही है। विज्ञान का अधिक से अधिक उपयोग कर प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए किसानों से जुड़ी व्यवस्थाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। इसमें ड्रोन सर्वे, फसल सर्वे के कार्य शामिल है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों सहित जनसामान्य की रूचि और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान गतिविधियों का विस्तार संभाग स्तर तक किया जाएगा। आने वाले समय में मध्यप्रदेश विज्ञान के क्षेत्र में सम्पन्न और समृद्ध बनें इस उद्देश्य से राज्य सरकार नवाचारों तथा अन्य गतिविधियों को निरंतर प्रोत्साहित करती रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार विज्ञान भवन में मीडिया से चर्चा में व्यक्त किए।

राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान 3 मार्च को मंत्रालय के सरदार पटेल पार्क में अब प्रात : 10 बजे से

भोपाल (नप्र)। मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र-गीत 'वन्देमातरम' एवं राष्ट्र -गान 'जन- गण-मन' का गायन 3 मार्च को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। पूर्व में यह गायन प्रातः 11 बजे होता था। अब समय परिवर्तित कर प्रातः10 बजे किया गया है। 1 एवं 2 मार्च को शासकीय अवकाश होने के कारण राष्ट्र- गीत एवं राष्ट्र-गान का आयोजन 3 मार्च का किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर राष्ट्र-गीत एवं राष्ट्र-गान का आयोजन सरदार पटेल पार्क में किया जाता है।

मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को सुविधा

बरगवां स्टेशन पर रुकने वाली इन 8 ट्रेनों की अवधि को बढ़ाया

भोपाल (नप्र)। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने पश्चिम मध्य रेलवे से गुजरने वाली आठ ट्रेनों के बरगवां स्टेशन पर ठहराव की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह बदलाव 1 मार्च 2025 से अगले आदेश तक प्रायोगिक रूप से लागू रहेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और यात्रा से पहले रेलवे स्टेशन, रेल मदद सेवा 139 या ह्ज्ञश्वस्र ऑनलाइन पोर्टल से अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

इस फैसले के तहत अहमदाबाद-कोलकाता, कोलकाता-मदार जंक्शन, संतरागाछी-अजमेर और हावड़ा-भोपाल एक्सप्रेस सहित आठ ट्रेनों के ठहराव का समय संशोधित किया गया है।

संशोधित ठहराव समय

ट्रेन संख्या और नाम	आगमन	प्रस्थान
19413 (अहमदाबाद-कोलकाता एक्सप्रेस)	रात 20:18	रात 20:20
19414 (कोलकाता-अहमदाबाद एक्सप्रेस)	सुबह 05:33	सुबह 05:35
19607 (कोलकाता-मदार जंक्शन एक्सप्रेस)	सुबह 05:33	सुबह 05:35
19608 (मदार जंक्शन-कोलकाता एक्सप्रेस)	रात 20:18	रात 20:20
18009 (संतरागाछी-अजमेर एक्सप्रेस)	सुबह 05:33	सुबह 05:35
18010 (अजमेर-संतरागाछी एक्सप्रेस)	रात 20:18	रात 20:20
13025 (हावड़ा-भोपाल एक्सप्रेस)	सुबह 05:33	सुबह 05:35
13026 (भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस)	रात 20:18	रात 20:20

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले संशोधित समय सारणी की पुष्टि कर लें, जिससे किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

पैक्स कर्मचारी उग्र आंदोलन की राह पर

सीहोर (नप्र)। साठ फीसदी पदों पर मौजूदा कर्मचारियों की भर्ती और नियमित वेतनमान को लेकर सहकारिता विभाग के पैक्स कर्मचारी एक बार फिर उग्र आंदोलन की तैयारी में है। पैक्स कर्मचारी 5 मार्च को मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री और विंध्याचल भवन का घेराव कर सकते हैं। पैक्स कर्मचारी जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी ने बताया कि अंतिम प्रयास मुख्यमंत्री और विभाग मंत्री से मुलाकात करना है। इसके बाद कर्मचारी आगे की रणनीति बनाने के लिए निरंतर अप्रत्यक्ष तौर पर बैठक कर रहे हैं। कर्मचारियों ने पीड़ा बताई है कि कोरोना जैसी महामारी के बीच जोखिम उठाकर कम किया। सरकार के हर आदेश का पालन करते हुए गरीब जनता और किसानों

की सेवा की। इस दौरान कई की जान भी गई। उसके बाद भी पीओएस मशीन में उक्त खाद्यान्न को कम नहीं किया गया। आरोप है कि सरकार ने मांगों के निराकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि वर्ष 2023 में सरकार से जो समझौता हुआ था। उसके अनुसार कर्मचारियों को वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। सरकार में विभाग अधिकारियों और मंत्रियों के बीच 60 फीसदी भर्ती का भी समझौता हुआ था। उसका भी पालन नहीं किया गया है। जबकि पैक्स संस्थाओं के कर्मचारी नियमित पदों पर काम करने की प्रतीक्षा में रिटायर हो रहे हैं। पूर्व सरकार ने दो बार तिथि तय की। लेकिन उनकी महापंचायत नहीं बुलाई गई। इन तमाम समस्याओं को लेकर अब आंदोलन करना ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है।

जीआईएस-भोपाल ने किया मध्यप्रदेश में सड़क अवसंरचना के नये युग का सूत्रपात : मुख्यमंत्री

1 लाख करोड़ रूपये के ऐतिहासिक एमओयू से प्रगति का मार्ग होगा प्रशस्त

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश तेजी से एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। राज्य के प्रत्येक कोने को आपस में जोड़ने और आर्थिक विकास को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए आधुनिक सड़क अवसंरचना तैयार है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल के पहले ही दिन, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ 1 लाख करोड़ रूपये के ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एमओयू राज्य में 4010 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं के निर्माण और विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इससे मध्यप्रदेश भविष्य में न केवल देश का, बल्कि दक्षिण एशिया का एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ये समझौते केवल सड़कें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार, रोजगार सृजन और बेहतर जीवनशैली के लिए आधार स्तंभ साबित होंगे। उन्होंने कहा कि जब कोई राज्य मजबूत सड़क नेटवर्क से जुड़ता है, तो वहां व्यापार, निवेश और उद्योगों की वृद्धि भी स्वाभाविक रूप से होती है। हमारा लक्ष्य मध्यप्रदेश को भारत का सबसे विकसित और आधुनिक राज्य बनाना है, और यह समझौता उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आधुनिक सड़क परियोजनाएं जो मध्यप्रदेश के भविष्य को आकार देंगी- जीआईएस-भोपाल में हुए इन ऐतिहासिक एमओयू से कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का विकास होगा। जीआईएस-भोपाल में सड़क अवसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर हुए है। इनमें इंदौर-भोपाल ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर, भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर, प्रयागराज-जबलपुर-नागपुर कॉरिडोर, लखनादौन-रायपुर एक्सप्रेसवे, आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग, उज्जैन-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग, इंदौर रिंग रोड

(पश्चिमी और पूर्वी बायपास), जबलपुर-दमोह राष्ट्रीय राजमार्ग, सतना-चित्रकूट राष्ट्रीय राजमार्ग, रीवा-सिद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्वालियर शहर के पश्चिमी छोर पर 4-लेन बायपास शामिल है।

नवीन सड़क परियोजनाएं न केवल मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों से जोड़ेंगी, बल्कि राज्य के प्रमुख शहरों को भी आपस में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। इससे यात्रा का समय घटेगा, लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन की लागत कम होगी, तथा कृषि, उद्योग, पर्यटन और व्यापार क्षेत्रों को नए अवसर मिलेंगे।

राज्य के आर्थिक विकास में योगदान- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कोई भी राज्य तभी प्रगति करता है जब वहाँ सशक्त बुनियादी ढांचा, कुशल परिवहन प्रणाली और मजबूत आर्थिक मॉडल उपलब्ध होते हैं। इन समझौतों से मध्यप्रदेश को एक नए औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब सड़कें बेहतर होंगी, तो उद्योगों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में आसानी होगी। इससे मध्यप्रदेश में नए उद्योग स्थापित होंगे और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। किसान अपने उत्पादों को तेजी से मंडियों और शहरों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। राज्य की पर्यटन स्थलों तक पहुँचने में सुगमता आएगी। इससे पर्यटन उद्योग को भी नया जीवन मिलेगा। इस परियोजना के तहत हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। सड़क निर्माण के दौरान इंजीनियर, श्रमिक, तकनीकी विशेषज्ञ और स्थानीय उद्यमी इससे लाभान्वित होंगे। नई सड़क परियोजनाओं से लॉजिस्टिक्स, होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा।

टाइम बाउंड प्रोजेक्टः समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार तेज़ी से परियोजनाओं को लागू करने और समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सभी परियोजनाओं को विश्व स्तरीय तकनीक, टिकाऊ निर्माण प्रक्रियाओं और उच्च गुणवत्ता वाले मानकों के साथ विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और संबंधित विभागों को हर आवश्यक सहायता प्रदान कर ये परियोजनाएँ तय समय सीमा के भीतर पूरी हों।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गति और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'विकसित भारत' मिशन का म.प्र प्रमुख केन्द्र- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज़ी से वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश इस योजना का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का सपना भारत को एक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। जीआईएस-भोपाल में हुए एमओयू उसी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहल है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद, मध्यप्रदेश देश की सबसे आधुनिक और कुशल परिवहन प्रणाली वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा।

भविष्य की दृष्टिः आत्म-निर्भर और विकसित मध्यप्रदेश-मध्यप्रदेश में इन ऐतिहासिक समझौते (एमओयू) के साथ एक नए युग की शुरुआत हो रही है। ये परियोजनाएँ राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक उज्जवल भविष्य देने का मार्ग प्रशस्त करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कितेज़, सुरक्षित और विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क, बेहतर लॉजिस्टिक्स और व्यापार के अवसर, उद्योगों के लिए आसान परिवहन और निर्यात के नए मार्ग, सड़क निर्माण से लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर और हर नागरिक के लिए सुगम और सुविधाजनक यात्रा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह परियोजनाएँ केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीनी स्तर पर इनका प्रभाव हर गाँव, हर शहर और हर नागरिक तक पहुँचे।

42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप

भोपाल के बड़े तालाब पर होगा 25 राज्यों की रोइंग टीमों का महामुकाबला

3 से 7 मार्च तक होगा आयोजन, मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे शुभारंभ,मंत्री सारंग ने की तैयारियों की समीक्षा

भोपाल (नप्र)। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को खेल एवं युवा कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर 42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि खिलाड़ियों और कोच के ठहरने, भोजन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही, प्रतियोगिता का सजीव प्रसारण एलईडी स्क्रीन के माध्यम से बोट क्लब सहित शहर के प्रमुख चौराहों पर किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक खेल प्रेमी इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले सकें। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक श्री रवि कुमार गुप्ता, संयुक्त संचालक श्री बी.एल. यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

3 से 7 मार्च तक 25 राज्यों के 500 खिलाड़ी होंगे शामिल-मंत्री श्री सारंग ने बताया कि बड़े तालाब स्थित मध्यप्रदेश राज्य वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी, बोट क्लब पर 3 मार्च से 7 मार्च तक 42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 3 मार्च को प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ी रोइंग, क्याकिंग-केनोइंग, सेलिंग और स्लालम खेलों की विशेष प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर खेल प्रेमियों को जल क्रीड़ा का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि चैंपियनशिप में 25 राज्यों से लगभग 500 प्रतिभागी भाग लेंगे। जिसमें रोइंग के कुल 14 इवेंट होंगे। यह चैंपियनशिप देश के शीर्ष रोवर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगी।

इन कैटेगरी में होगी प्रतियोगिताएं-42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में सीनियर पुरूष, सीनियर महिला और पैरा रोइंग स्पर्धाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित की जाएँगी। सभी स्पर्धाएं 2000 मीटर की दूरी पर आयोजित की जाएँगी। सीनियर मेन्स वर्ग में सिंगल स्कल्स (MvX), डबल स्कल्स (MwX), कॉक्सलेस पेयर्स (M2-), कॉक्सलेस फोर्स (My-), लाइटवेट मेन डबल स्कल्स (LM2X), ओपन डबल स्कल्स (M2X - सिविलियन), कॉक्सलेस फोर्स (M4- - सिविलियन), क्वाड्रपल स्कल्स (M4X) और कॉक्स्ड ईट्स (M3+) शामिल हैं।

सीनियर महिला वर्ग में सिंगल स्कल्स (W1X), डबल स्कल्स (W2X), कॉक्सलेस पेयर्स (W2-), कॉक्सलेस फोर्स (W4-), लाइटवेट वुमन डबल स्कल्स (LW2X), क्वाड्रपल स्कल्स (W4X) और कॉक्स्ड ईट्स (W8+) की स्पर्धाएं होंगी। पैरा रोइंग स्पर्धाओं में पैरा मेन सिंगल स्कल (PR3M1X) और पैरा वुमन सिंगल स्कल (PR3W1X) प्रतियोगिताएँ होंगी।

कुक्षी से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक 135 किमी चलेगा क्रूज

एमपी में 100 करोड़ का निवेश प्रस्ताव; इलेक्ट्रिक-सोलर के होंगे

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में क्रूज प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अयोध्या क्रूज लाइन्स ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीएसआई) में प्रस्ताव दिया है। ऐसे में 135 किमी लंबे कुक्षी से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी समेत 6 में से किसी एक रूट पर क्रूज पानी की लहरों पर दौड़ने लगेगा। वहीं, 70 करोड़ रुपए का निवेश वाटर एक्टिविटी पर भी किया जाएगा। खास बात ये है कि क्रूज इलेक्ट्रिक या सोलर से ही चलेंगे। डीजल इंजन वाले क्रूज-मोटर वोट्स पर एमपी में रोक लगी है। जिस कंपनी ने एमपी में क्रूज चलाने का प्रस्ताव दिया है, उसके अभी सरयू नदी पर 2 क्रूज चल रहे हैं। वहीं, उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर जनपद में गंगा नदी के बृज घाट से राम घाट तक 2 क्रूज, हाउस बोट्स और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करने वाली है।

पत्नी की हत्या कर बेटे से कहा-मां को मार डाला

जबलपुर में खाना नहीं देने पर आरोपी ने फावड़े से ताबड़तोड़ वार किए

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर में खाना नहीं देने से नाराज शख्स ने पत्नी की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। आरोपी दूसरे कमरे में जाकर सो गया। इसके बाद घर में ताला लगाकर निकल गया। तीन किलोमीटर दूर बेटे के घर जाकर कहा- तुम्हारी मां को मार डाला, लाश घर पर पड़ी है। जाकर देख लो।

सुशील यादव

पुलिस ने बेटे की शिकायत पर गुरुवार देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना गोरखपुर के मांडवा बस्ती में बुधवार रात की है। यहां सुशील यादव (54) ने घर आकर पत्नी रमा (50) से खाना मांगा। जब काफी देर तक रमा ने खाना नहीं दिया तो सुशील ने उसे धक्का दे दिया। पत्नी नाराज होकर कमरे में चली गई। सुशील ने फावड़ा उठाया और रमा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

बेटे से कहा- चाबी लो, घर पर ताला लगा है- पत्नी को अधमरा छोड़कर आरोपी सुशील पहले तो दूसरे कमरे में जाकर सो गया। गुरुवार को दिन में वह रमा के पास गया। उसे अचेत देखकर सुशील समझ आ गया कि उसकी मौत हो गई है। दोपहर को घर में ताला लगाकर वह बेटे शुभम यादव के घर गया और हत्या की जानकारी दी। उसने चाबी देकर कहा कि घर पर ताला लगा है।पहले तो शुभम को अपने पिता की बात पर भरोसा नहीं हुआ। आनन-फानन में वह राजा मांडवा बस्ती पहुंचा। कमरे में जाकर देखा तो मां मृत हालत में उसकी मां पड़ी हुई थी। बेटे ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की तलाश शुरू की गई।

विवाद के कारण अलग रहता है बेटा-सुशील यादव और रमा का 30 साल पहले विवाह हुआ था। मदन महल से विस्थापित होने के बाद दोनों सात मांडवा बस्ती में आकर रहने लगे। दो बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे की बीमारी के कारण मौत हो गई।

रीवा में बहू की हत्या में ससुर गवाही ना दे, इसलिए उसे ही मार डाला...

रीवा (नप्र)। मनगवां थाना क्षेत्र के मनिकवार गांव में जघन्य हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना में उस वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जो कि अपने ही बेटे और बहू पर प्राणघातक हमले का गवाह रहा।

उस घटना में वृद्ध की बहू की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि इस घटना के आरोपित चाहते थे कि वृद्ध ससुर न्यायालय में वो गवाही न दे, लेकिन वो पीछे हटने तैयार नहीं रहा। इसी रंजिश के चलते गुरुवार की देर रात ससुर की भी हत्या कर दी गई।

3 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देकर किया कौशल उन्नयन

2383 हायर सेकण्ड्री स्कूलों में इस वर्ष शुरू की गई व्यावसायिक शिक्षा

भोपाल (नप्र)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये इस वर्ष 3 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दिलाई गई है। इस शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के 2383 हायर सेकण्ड्री स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विद्यार्थियों को सुलभता से रोजगार उपलब्ध कराने के लिये व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि तेजी से बढ़ती हुई विश्व की अर्थव्यवस्था में हम सभी का किस प्रकार से योगदान हो। बढ़ती हुई आबादी के साथ जनता के लिये उनकी शिक्षा, कौशल तथा आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार का सृजन एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसी चुनौती का सामना करने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं में विद्यार्थियों को उनकी रूचि के अनुसार वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिये स्कूलों में नये ट्रेडों की शुरूआत की गई है। इसके लिये प्रशिक्षकों की सेवा भी ली जा रही है।

शैक्षणिक गुणवत्ता के लिये प्रशिक्षण पर जोर-प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये इस वर्ष 40 हजार से अधिक शिक्षकों को विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिलाया गया है। प्रशिक्षण की व्यवस्था में प्रारंभिक तौर पर मास्टर ट्रेनर्स भी तैयार किये गये हैं।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने डेटा स्टोरेज सटीकता बढ़ाने के लिए विकसित की सेमीकंडक्टर चिप

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तकनीकी शिक्षा में निरंतर स्थापित हो रहे नए आयाम : मंत्री परमार

तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री परमार ने नवाचारी शोध के लिए विश्वविद्यालय परिवार को दी शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिवार को, सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने की नवाचारी शोध करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं हैं। मंत्री श्री परमार ने शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. वैभव नीमा एवं उनके सहयोगी शोधार्थियों के पुरुषार्थ से सृजित यह नवाचार, तकनीक के क्षेत्र में निश्चित ही अपनी महती उपयोगिता सुनिश्चित करेगा। श्री परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के यशस्वी नेतृत्व में, राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और इसमें नवाचार, शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और निरंतर नए आयाम स्थापित कर रही है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं प्रगति के साथ, शैक्षणिक एवं अकादमिक स्तर पर उत्तरोत्तर गुणवत्ता वृद्धि हो रही है। श्री परमार ने कहा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी शोध करना, प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। प्रदेश के समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थान भी शोध एवं नवाचार की दिशा में, नवीन आयाम स्थापित करने के लिए प्रयास करें।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) इंदौर ने एक सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन की है, जो डेटा स्टोरेज की सटीकता को बढ़ाती है, जिससे सैटेलाइट इमेजरी और बायोमेडिकल एप्लीकेशन को फायदा होता है। सेमीकंडक्टर चिप को डीएवीवी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) के वीएलएसआई ग्रुप द्वारा टाइनी टेपआउट शैक्षणिक परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह परियोजना सेमीकंडक्टर डिज़ाइन को अधिक सुलभ और किफायती बनाने का लक्ष्य रखती है। इस उपलब्धि के साथ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय उन प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने सफलतापूर्वक एक फैब्रिकेटेड सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन किया है।

सेमीकंडक्टर चिप का विकास और विशेषताएँ-यह चिप स्काईवाटर की 130एनएम तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो डेटा त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उन्हें सुधार सकती है। यह सफलता देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करती है और विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तकनीक में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करती है।

शोधार्थी टीम और अनुसंधान प्रक्रिया-देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आईईटी के फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर्स समेत सात सदस्यों की टीम ने इस चिप को डिज़ाइन किया है और इसे फैब्लैब मलेशिया से फैब्रिकेट करवाया है। इस टीम का नेतृत्व डॉ. वैभव नीमा ने किया, उनके साथ प्रोफेसर रवि सिंदल, सुश्री प्रियंका शर्मा, श्री आशीष पंचाल और पीएचडी स्कॉलर्स श्री ऋषभ बडज़ातिया, श्री अमित साहनी और सुश्री आस्था गुप्ता शामिल हैं। शोधार्थी टीम ने पिछले लगभग डेढ़ साल से इस सेमीकंडक्टर चिप को डिजाइन करने की दिशा में समर्पित परिश्रम किया। आईईटी के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शैलेश सिंह चौहान ने भी इस परियोजना में मार्गदर्शन दिया है, जो वर्तमान में स्वीडन विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। इस सेमीकंडक्टर चिप की डिज़ाइन तैयार करने में आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर डॉ संतोष कुमार विश्वकर्मा द्वारा निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया गया है।

अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोग-शोधार्थी टीम के नेतृत्वकर्ता डॉ. वैभव नीमा ने बताया कि हमें निर्मित सेमीकंडक्टर चिप प्राप्त हो गई है, इसलिए अब हम परीक्षण और पेटेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। यह विकास हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खोलेगा, जो आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों पर काम कर सकते हैं और उन्हें प्रोटोटाइप में बदल सकते हैं।डॉ. वैभव नीमा ने बताया कि आईईटी को इस परियोजना के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से चिप्स टू स्टार्टअप्स कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। इस योजना का उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में 85 हजार इंजीनियरों को वीएलएसआई और एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। इस पहल से सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे एसओसी सिस्टम डिजाइन को स्नातक, मास्टर्स और अनुसंधान स्तर पर सीखने में सहायता मिलेगी। यह भारत में फैबलेस डिज़ाइन स्टार्टअप्स के विकास को भी बढ़ावा देगा।

चिप के लाभ और भविष्य की योजनाएँ-डॉ. वैभव नीमा ने बताया कि इस चिप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह डेटा सटीकता सुनिश्चित कर सकती है, जो सैटेलाइट इमेजिंग, बायोमेडिकल रिसर्च और एआई-आधारित एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में सटीक डेटा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक है।

इसकी स्वतः त्रुटि पहचान और सुधार तकनीक से डेटा के खराब होने के जोखिम को कम करती है। अगले चरण में, वीएलएसआई टीम चिप का परीक्षण और सत्यापन करेगी। एक बार चिप को मान्यता मिलने के बाद इसे, चिप को औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए पेश किया जाएगा, जो संभवतः स्वास्थ्य सेवा और दूरसंचार क्षेत्रों के लिए लाभकारी होगा। आईईटी, वीएलएसआई टीम अगले वर्ष तक दो और परियोजनाओं को पूरा करने की योजना बना रही है।

॥ मंदिरम् ॥

47

बसुकेदार मंदिर, उत्तराखंड

बसुकेदार मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार गांव में स्थित है। यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड के दिव्य धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच राजमार्ग पर स्थित है। यह दो धाम के रास्ते में स्थित है। हिंदू धर्म में इस मंदिर का विशेष महत्व है, खासकर भगवान शिव के भक्तों के लिए। यह मंदिर भगवान शिव का विशेष रूप से प्रतिष्ठित मंदिर है। इस मंदिर का नाम भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों से लिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर के गढ़ाकोटा में श्री गणेश अष्ट विनायक देव मन्दिर में दर्शन किए।

ट्रक में घुसी कार, भोपाल के 4 लोगों की मौत

एक घंटे तड़पते रहे, जेसीबी से निकालनी पड़ी कार

भोपाल (नप्र)। भोपाल के चार लोगों की यूपी के महोबा में सड़क हादसे में मौत हो गई। प्रयागराज से लौटते समय उनकी कार सामने से आ रहे ट्रक में घुस गई। ट्रक कार को 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। कार बुरी तरह उसमें फंस गई। चारों लोग एक घंटे तक तड़पते रहे। घटना शुक्रवार सुबह कानपुर-सागर हाईवे पर बस स्टैंड के पास हुई। पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला। तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

भोपाल के रहने वाले सभी- भोपाल के रहने वाले नरेश नागर, पूजा नागर (23) और ड्राइवर अवधेश नागर पिता बाबूलाल और एक महिला कार से प्रयागराज गए थे। वे वहां से लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी।

तेज रफ्तार के कारण हादसा- एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार ने बताया कि कानपुर-सागर हाईवे पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार के कारण कार सीधे ट्रक के अगले हिस्से में जा घुसी। जिससे 4 लोगों की मौत हो गई है। यह सभी प्रयागराज से भोपाल जा रहे थे।

म.प्र.में मोहन सरकार का बजट 12 मार्च को आएगा

4 लाख करोड़ से अधिक का होगा, गौवंश-पर्यावरण संरक्षण, झुग्गीमुक्त शहर पर फोकस की संभावना

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट 12 मार्च आएगा। राज्य सरकार का वित्त विभाग नए बजट की तैयारियों में जुटा हुआ है। मोहन कैबिनेट अगले दस दिनों में सरकार के पहले पूर्ण बजट को मंजूरी देगी, जिसे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में पेश किया जाएगा।

यह बजट चार लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट भी 10 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इस बार बजट में गोवंश संरक्षण, पर्यावरण, धरोहर व पर्यटन स्थलों के संवर्धन व संरक्षण, रोजगार, ई-परिवहन, झुग्गीमुक्त शहरों सहित अनेक मुद्दों पर फोकस देखने को मिल सकता है।

पिछले साल मार्च में नहीं आ सका था बजट- मोहन यादव सरकार पिछले साल अपना पूर्ण बजट मार्च में नहीं ला पाई थी। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनावों थे, जिनके चलते पहले तीन माह के खर्च के लिए लेखानुदान पारित किया गया था और फिर एक जुलाई को बजट सत्र बुलाकर तीन जुलाई को बजट पेश किया गया था।

इस साल भी फाइनेंस टीम लीडर मनीष- एमपी का बजट तैयार करने की जिम्मेदारी पिछले साल मनीष सिंह के पास थी। वह इस समय स्टडी लीव पर हैं। ऐसे में इस बार यह जिम्मा सीएम मोहन ने मनीष रस्तोगी को सौंपा है। रस्तोगी की टीम बजट के लिए अब तक मिले सुझावों को कंपाइल कराने का काम कर चुकी है और मुख्यमंत्री तथा डिप्टी सीएम से चर्चा के बाद इसे फाइनल करने का काम किया जाएगा। इसको लेकर वित्त विभाग के प्रमुख सचिव रस्तोगी के साथ सीएम मोहन की बैठकों का दौर अगले दस दिनों तक कई बार चलने की उम्मीद है।

बजट में इन पर फोकस करेगी मोहन सरकार- मोहन सरकार इस बजट में बेरोजगारी कम करने को लेकर किए गए सरकार के प्रयासों पर फोकस करने वाली है। इसके लिए एक लाख पदों पर भर्ती के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड, पीएससी और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भर्ती करने के विज्ञापन निकाले जा चुके हैं।

वर्ष 2025-26 के बजट में गोवंश संरक्षण, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के विकास और पर्यटन पर भी फोकस होगा।

बजट में नई योजनाओं के साथ हर विभाग की ओर से चालू वित्त वर्ष के लिए किए गए बजट प्रावधान और खर्च की गई राशि का ब्योरा भी शामिल किया जाएगा।

प्रदेश में ई-परिवहन, झुग्गीमुक्त शहरों की प्लानिंग और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विज्ञान और तकनीकी सुविधाओं पर भी बजट में सरकार अपनी नीति का खुलासा करेगी।

सरकार यह जानकारी जुटा चुकी है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक विभाग के कुल बजट का प्रावधान कितना है और कितनी राशि खर्च हो चुकी है।

सभी विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं और उसके लक्ष्य व उपलब्धि की जानकारी भी ली जा चुकी है।

यह डिटेल भी सरकार विभागों से मांग चुकी है कि प्रदेश में केंद्र प्रवर्तित योजना और केंद्र क्षेत्रीय योजनाओं की स्थिति और प्रगति की क्या रिपोर्ट है?

विभागों की नई योजनाओं के संबंध में शार्ट नोट और तथ्यात्मक जानकारी मंगाई जा चुकी है।

एंबुलेंस में डिलीवरी, परिजन से धुलवाई गाड़ी

वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर-अटेंडर को हटाया

मैहर (नप्र)। मैहर जिले में अमानवीय घटना सामने आई है, जहां एक एंबुलेंस ड्राइवर ने मानवता को शर्मसार कर दिया। जिले के अमरपाटन सिविल अस्पताल में भर्ती होने पहुंची प्रसूता के परिजनों को ही एंबुलेंस साफ करने को मजबूर कर दिया गया।

घटना अमरपाटन ब्लॉक के पगरा गांव की है। गुरुवार दोपहर गर्भवती ममता कोल को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी डिलीवरी हो गई। अस्पताल पहुंचने पर मां और नवजात को भर्ती कर लिया गया। इसके बाद एंबुलेंस ड्राइवर ने प्रसूता के परिजनों से वाहन की सफाई करवाई। वे नल से पानी भरकर एम्बुलेंस धोने लगे, जिसका वीडियो वायरल हो गया।

सरकार ने अनुबंधित संस्था को नोटिस किया जारी

सीएमएचओ डॉ. एलके तिवारी ने कहा कि एंबुलेंस की सफाई की जिम्मेदारी ड्राइवर और स्टाफ की होती है। प्राथमिक जांच के एम्बुलेंस ड्राइवर और अटेंडर को पद से हटा दिया गया है। उन्होंने राज्य शासन स्तर से अनुबंधित संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

संजय कुमार शुक्ला अपर मुख्य सचिव बनाए गये

भोपाल (नप्र) । राज्य शासन ने नगरीय प्रशासन, आवास, आर्थिक एवं सांख्यिकी और विमानन मंत्रालय के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ल को अपर मुख्य सचिव पद पर यथावत पदोन्नति किया है। वहीं शासन ने दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एडिशनल डीजी पवन कुमार श्रीवास्तव अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय और मनीष शंकर शर्मा रेल पुलिस मुख्यालय पदोन्नत कर स्पेशल डीजी बनाया है। पदोन्नत दोनों पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना यथावत है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025

छोटे उद्योगों के लिए बड़े अवसर तैयार: मुख्यमंत्री

मेड इन एमपी को वैश्विक पहचान, एमएसएमई को मिली नई दिशा, एमओयू पर हस्ताक्षर हुए

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जीआईएस भोपाल से एमएसएमई क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को और अधिक ऊचाईयाँ मिलेगी। इससे राज्य के युवाओं के उद्यमी बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए पीएम-मुद्रा, पीएम-विश्वकर्मा और एमएसएमई क्रेडिट गारंटी योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ पहले ही लांच की है। जीआईएस भोपाल में कई एमएसएमई कंपनियों से 21 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव आए। इनसे राज्य में 1.3 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, साथ ऐसे युवाओं को उद्यमी बनने के अवसर मिलेंगे जो अब तक नौकरी की तलाश में थे।

व्यापक बैठकें और तकनीकी नवाचार- जीआईएस भोपाल में 600 से अधिक बी-2-जी बैठकें और 5 हजार से अधिक बी-2-बी बैठकें आयोजित की गईं। इनमें उद्योगपतियों, निवेशकों और एमएसएमई कंपनियों ने भाग लिया। पहली बार एआई-आधारित बिजनेस मैच-मेकिंग टूल का उपयोग किया गया, जिससे सही साझेदारों को जोड़ने में सहायता मिली। इन बैठकों ने मध्यप्रदेश को एक वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एमएसएमई क्षेत्र में राज्य सरकार की विशेष पहल- मध्यप्रदेश सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। हाल ही में कैबिनेट में नई एमएसएमई पॉलिसी मंजूर की गई। नई एमएसएमई नीति में अविकसित भूमि का लघु, मध्यम और सूक्ष्म इकाइयों को आवंटन, फ्लैट आधारित उद्योग लगाने की अनुमति, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और रख-रखाव उद्योग संघों के माध्यम से, 53 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य, जिससे 86 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। नई नीति में औद्योगिक भूमि आवंटन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ई-बिडिंग प्रणाली लागू की गई।

प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को आसान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। टैक्स इंसेंटिव, लैंड अलॉटमेंट और 'ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस' में सुधार को ध्यान में रखकर एमएसएमई उद्यमियों की मदद के लिए नीति बनाई गई है। सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोमेशन को अपनाने की दिशा में पहल की जा रही है। नई पॉलिसी में राज्य सरकार एमएसएमई के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने के लिए विशेष योजनाओं पर कार्य कर रही है।

प्रमुख निवेशक कंपनियां

जीआईएस-भोपाल में कई एमएसएमई कंपनियों ने राज्य में निवेश के लिए रुचि दिखाई, जिनमें प्रमुख रूप से वकी प्राइवेट लिमिटेड (इंदौर), भगवती तीरथ पॉलि कंटेनर्स इंडस्ट्री, इवेट लिमिटेड (भोपाल), आहाराम मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (नीमच), डीटवी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (इंदौर) और ईजीटेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (भोपाल) शामिल हैं।

भविष्य की संभावनाएं

राज्य सरकार ने 2025 तक एमएसएमई क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, एमएसएमई सेक्टर के लिए समर्पित इनक्यूबेशन सेंटर्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 'मेड इन एमपी' अभियान को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल से मध्यप्रदेश को एमएसएमई के लिए एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने में मदद मिलेगी और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी।

इंदौर-खरगोन छापे में 400 करोड़ के बोगस बिल मिले

आयकर विभाग ने 100 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी किए हैं जब्त

भोपाल (नप्र)। आयकर विभाग ने इंदौर और खरगोन में की गई छापेमारी की कार्यवाही में 400 करोड़ रुपए के बोगस बिल और 100 करोड़ रुपए के प्रापर्टी के दस्तावेज जब्त किए हैं। दोनों ही जिलों में चार कारोबारियों के ठिकानों पर की गई कार्यवाही में 11.50 करोड़ रुपए के कैश व ज्वेलरी मिली है। जांच टीम ने इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इसके अलावा हुंडी से संबंधित रिकार्ड भी आयकर ने कब्जे में लिए हैं। विभाग के अफसरों की टीम ने 18 फरवरी को यह छापेमारी इंदौर में तीन ठिकानों पर और खरगोन जिले के भीकनगांव में की थी। इंदौर में सिंडीकेट प्रशांत शर्मा और हर्ष जैन, अवधेश दीक्षित तथा भीकनगांव में अनंत एग्रो इंडस्ट्रीज के संचालक रामस्वरूप अग्रवाल के ठिकानों पर 21 फरवरी यानी चार दिन तक कार्यवाही चली थी। जांच के दौरान आयकर विभाग की टीम को इन सबके ठिकानों पर 7.50 करोड़ रुपए कैश और 3.50 करोड़ रुपए की ज्वैलरी मिली है। इसके अलावा हुंडी के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।

कॉटन सप्लाई के 400 करोड़ के बोगस बिल- आयकर अधिकारियों को इस छापे में आर्गेनिक कॉटन सप्लाई के 400 करोड़ रुपए के बोगस बिल मिले थे। यह बोगस बिल कॉटन की सप्लाई किए बगैर जारी कर दिए जाते थे और इसका भुगतान दिखा दिया जाता था।

जर्मन शेफर्ड डॉग ने बाघ से परिवार की जान बचाई

घायल होकर भी जीत गया डॉग...बाघ को भागना पड़ा

उमरिया (नप्र)। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के निकट स्थित ग्राम भरहुत में बाघ शावक ने जब एक परिवार पर हमला करने की कोशिश की, तो डॉग ने सामने आकर पूरे परिवार की जान बचा ली। इस घटना में डॉग घायल हो गया। यह घटना दो दिन पहले की है, लेकिन डॉग के शरीर के घाव अभी भी ताजा हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए पशु चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बताया कि घायल डॉग को परिवार के लोग उपचार के लिए लेकर आए थे, तब इस घटना की जानकारी उनके सामने आई। उन्होंने बताया कि बाघ के हमले में डॉग के शरीर पर काफी गंभीर घाव बने हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है और वह कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा।

बाघ से लड़ गया डॉग- घटना की जानकारी देते हुए भरहुत निवासी शिवम बढ़गैया ने बताया कि वे सभी लोग रात में घर के अंदर थे। इसी दौरान जंगल से निकलकर एक बाघ गांव में पहुंच गया। इसके बाद वो उनके घर में घुस आया। इस दौरान उनके घर के परिसर में घूम रहा जर्मन शेफर्ड डॉग बाघ को देखकर भौंकने लग और बाघ का रास्ता रोक लिया।

डॉग को अपने सामने देखकर कुछ देर के लिए बाघ भी स्तब्ध खड़ा रह गया, लेकिन अचानक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। डॉग इस हमले से घबराया नहीं बल्कि उसने बाघ पर जवाबी हमला किया और उसे डराने की कोशिश की।

झपट्टा मारकर खींच ले गया बाघ- शिवम बढ़गैया ने बताया कि उनका जर्मन शेफर्ड डॉग वरिष्ठ होने के बावजूद बाघ का ज्यादा देर सामना नहीं कर पाया और एक झपट्टा मारकर बाघ डॉग को अपने साथ खींच ले गया। कुछ दूर ले जाकर बाघ ने डॉग को मारने की कोशिश की, लेकिन डॉग फिर पूरी ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ और बाघ के सामने गुर्राने लगा।

कुछ देर के प्रयास के बाद जब बाघ डॉग को मारने में सफल नहीं हुआ तो वहां से वापस लौट गया। डॉग और बाघ की इस लड़ाई के दौरान गांव के लोग जाग चुके थे और वे भी शोर मचाते हुए बाहर आ गए। जिसकी वजह से बाघ जंगल के अंदर चला गया।

आखिरकार पीथमपुर में जलाया जा रहा भोपाल का जहरीला कचरा

तीन स्टेप में पूरी होगी प्रोसेस, सुरक्षा के लिए 650 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

पीथमपुर (नप्र)। पीथमपुर के तारपुरा गांव में रामकी एनवायरो फैक्ट्री में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाना शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे कचरा भस्मक में डाला गया। इंसीनरेटर का तापमान अभी 900 डिग्री है।

दूसरे चरण में 1100 से 1200 डिग्री तापमान पर कचरा जलेगा। इसके बाद तीसरी स्टेप में इसे गैस फ्लू ड्रायर में डाला जाएगा। यहां कचरे को पानी और सोडियम सल्फाइड के घोल से गुजारेंगे। केमिकल के छन जाने के बाद राख को सुरक्षित जमीन में दफन कर दिया जाएगा।

मप्र प्रदूषण बोर्ड के अफसर मौजूद- फैक्ट्री के इंसीनरेटर में पहले ट्रायल रन में 10 टन कचरा नष्ट किया जाएगा। मौके पर मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी, धार के जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्र, एसपी मनोज कुमार सिंह समेत अन्य अफसर मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम दो विशेषज्ञ डाक्टरों के साथ कंपनी परिसर के बाहर हैं।

फैक्ट्री परिसर के अंदर स्पेशल आर्म्ड फोर्स के 130 जवान तैनात हैं। परिसर के बाहर डीएसपी रैंक के अधिकारी भी हैं। आसपास के सभी रास्तों की नाकाबंदी की गई है। बिना पूछताछ किसी को भी कंपनी परिसर के पास जाने की इजाजत नहीं है। वहीं, पीथमपुर शहर में इंदौर देहात और धार जिले के 24 थानों के पुलिसकर्मी सुरक्षा-व्यवस्था संभाल रहे हैं। करीब 650 जवान शहर के अलग-अलग चौराहों, कॉलोनियों और तारपुरा गांव में मौजूद हैं। 10 से ज्यादा गाड़ियां शहर भर में गश्त कर रही हैं।

सीएम बोले- डराने का काम कर रही कांग्रेस

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा- यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर सरकार कोर्ट का बहाना बना रही है। इसके पीछे उनके नेताओं के आर्थिक हित छिपे थे। मैं स्थानीय नेताओं और प्रशासन को चुनौती देता हूं कि रामकी कंपनी के आस-पास के 10 किलोमीटर के भू-जल की जांच की जाए अगर उसमें कैंसर के तत्व नहीं मिलेंगे तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूगा।

इस पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने पलटवार किया- भोपाल में 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड के कारण मारे गए थे। इसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी। उन्होंने एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ दिया था, दूसरी तरफ अब डराने का काम कर रहे हैं। माफी तो उन्हें मांगनी ही चाहिए।